मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक

वर्ष: 42 अंक: 45 नई दिल्ली (कुल पेज 16) 6 – 12 नवम्बर 2022 मूल्य 7 रुपये

अंदर के पेजों में

आरपीडी: भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के मार्गदर्शक.....5

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं कांग्रेस में पारित प्रस्ताव.....8–9

2024 के चुनाव में भाजपा को हराओ: भाकपा

हमारे विशेष संवाददाता द्वारा

नई दिल्ली: 27 अक्टूबर 2022 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय अजय भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी. राजा ने कहा कि 14 से 18 अक्टूबर 2022 तक आयोजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं कांग्रेस का संदेश है कि 2024 के आम चुनाव में भाजपा को हराने के लिए पूरी कोशिश की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के अन्य राष्ट्रीय सचिवगण–अमरजीत कौर और बिनोय विश्वम भी उपस्थित थे।

डी. राजा ने कहा कि भाजपा–आरएसएस गठजोड़ धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और देश के संविधान को गंभीर खतरा पेश कर रहा है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार विनाशकारी नीतियों पर चल रही हैं जिसके कारण देश चौतरफा संकटों में घिरता जा रहा है।

अर्थव्यवस्था अस्तव्यस्त है। भारतीय रुपए का मूल्य इतना नीचे गिर गया है कि देश के सम्मान को ठेस पहुंच रही है। बेरोजगारी अभूतपूर्व ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है जिसके कारण देश के नौजवानों में भारी बेचैनी है। विश्व भूख सूचकांक में देश का स्थान एक शर्मनाक स्तर पर पहुंच गया है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। कारपोरेटों और बड़े कारोबारी घरानों को राष्ट्रीय परिसंपत्तियों और देश की धन–दौलत लूटने की छूट मिली हुई है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र का विघटन करने और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निजीकरण करने पर तुली है।

उन्होंने कहा कि भाजपा–आरएसएस गठजोड़ संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को कमजोर करने और भारतीय राज्य के चरित्र, जो संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष कल्याणकारी एवं संघात्मक राज्य है, को ही बदलने पर आमादा है।

दलितों, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। नागरिकों के संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। देश आज कारपोरेट– सांप्रदायिक फासिज्म का उभार होते देख रहा है।

इस स्थिति का तकाजा है कि देश की जनता को तबाही से बचाने के लिए आज पहला लक्ष्य यह होना चाहिए कि भाजपा–आरएसएस गठजोड़ को सत्ता से हटाया जाय।

डी.राजा ने आगे कहा कि पार्टी कांग्रेस द्वारा पारित राजनीतिक प्रस्ताव ने देश की सभी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक पार्टियों, क्षेत्रीय पार्टियों, वामपंथी ताकतों और सामाजिक आंदोलनों का आह्वान किया है कि वे एकजुट हों और 2024 के संसदीय चुनाव में भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों को हराने के लिए एक मजबूत और एकताबद्ध लड़ाई की तैयारी करें।

सम्मान के साथ जीवन जीने के हमारी जनता के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, आवासन, भोजन और जमीन जैसे रोजी–रोटी के बुनियादी मुद्दों को उठाया जाना चाहिए।

पार्टी संगठन को मजबूत करो

पार्टी कांग्रेस ने पार्टी संगठन को मजबूत करने संबंधी कदमों पर विस्तारपूर्वक विचार किया। भारतीय संदर्भ में मार्क्सवाद–लेनिनवाद को लागू करते हुए पार्टी को वर्ग शोषण को समाप्त करने, जाति उन्मूलन और पितृसत्तात्मकता को खत्म करने के लिए अपने संघर्ष को तेज करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि 2025 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपनी शताब्दी जयंती मनाने जा रही है। उस समय तक अपनी सदस्यता को 10 लाख तक बढ़ाकर और संसद, राज्य विधान सभाओं और देश भर में स्थानीय निकायों में अपना अच्छा–खासा प्रतिनिधित्व बनाकर पार्टी को मजबूत किया जाना चाहिए।

वाम एकता एवं कम्युनिस्ट एकता को मजबूत करो

डी. राजा ने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं कांग्रेस ने सभी वामपंथी पार्टियों से अपील की है कि वामपंथी एकता को मजबूत करें। कारपोरेट–सांप्रदायिक फास्टिस ताकतों के खिलाफ संघर्ष में कम्युनिस्ट आंदोलन की एकता अत्यंत आवश्यक है। पार्टी कांग्रेस ने एक सिद्धांतनिष्ट आधार पर कम्युनिस्ट आंदोलन के एकीकरण के संबंध में पार्टी के दृष्टिकोण को दोहराया।

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केरल की एलडीएफ सरकार के बीच चल रहे विवाद के संबंध में एक प्रश्न के उत्तर में डी. राजा ने कहा कि पिछले आठ वर्षों में हमने देखा है कि जहां कोई संकट नहीं है वहां संकट पैदा करने के लिए राज्यपाल अनुचित रास्तों पर चल रहे हैं। राज्यपाल का पद अनावश्यक है और संसदीय लोकतंत्र में अब इसकी कोई जरूरत नहीं रह गई है।

उन्होंने कहा कि पार्टी कांग्रेस में इस मुद्दे पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई।

उन्होंने आगे कहा कि ''यह समझने की जरूरत है कि राज्यपाल के काम क्या हैं? राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार काम करता है। अपने संवैधानिक कर्तव्यों के खिलाफ जाते हुए वह जानबूझ कर एक निर्वाचित सरकार के साथ विवाद पैदा करना चाहते हैं।'' उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अनुरोध किया कि वह तत्काल खान के खिलाफ कार्रवाई करें क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति की संतुष्टि के अनुसार करता है।

उन्होंने कहा कि ''बुनियादी तौर पर, एक संवैधानिक संसदीय लोकतंत्र में हमें राज्य पाल की जरूरत नहीं। वे दिल्ली में सत्ता पर बैठी पार्टी के राजनैतिक नियुक्तियां होते हैं। पिछले आठ वर्षों में हमने देखा है कि जहां कोई संकट नहीं है वहां संकट पैदा करने के लिए राज्यपाल अनुचित रास्तों पर चल रहे हैं।''

इभी हाल के दिनों में चुनाव आयोग ने भी राजनीतिक पार्टियों के मामलों में दखलदांजी शुरू कर दी है जबकि संविधान के अनुसार आयोग का काम केवल मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव कराना है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा अपने दायरे से बाहर जाकर काम करने पर आपत्ति जताते हुए पार्टी ने 21 अक्टूबर 2022को आयोग को एक सख्त पत्र लिखा है।

पत्र में पार्टी ने चुनाव आयोग का ध्यान इस तथ्य की तरफ आकर्षित किया है कि संविधान की धारा 327 ने संसद को अधिकार दिया है कि वह चुनावों के संबंध में प्रावधान करे; यह अधिकार चुनाव आयोग को नहीं दिया गया। धारा 324 में चुनाव आयोग के काम के संबंध में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ''निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण'' चुनाव आयोग में निहित होगा''। अतः पार्टी का विचार है कि चुनावी घोषणापत्र में कोई पार्टी क्या कहती है इसके संबंध में चुनाव आयोग यदि कोई बात कहता है तो वह अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाता है, अतः यह संसद और राजनीतिक पार्टियों की शक्तियों पर अतिक्रमण है।

महान अक्टूबर क्रांति जिंदाबाद

फासीवाद और मुसोलिनी

संपादकीय

आज फिर से एक बार अक्टूबर का इकतीसवां दिन आ गया है। यह दिन ''रोम की ओर'' मार्च का था, जब मुसोलिनी इटली की राजधानी की ओर अपनी काली कमीज वालों की फौज लेकर बढ़ रहा था। आज से सौ साल पहले, 28 अक्टूबर, 1922 को इटली के राजा ने मजबूर होकर मुसोलिनी को अपने राज्य का प्रधानमंत्री घोषित किया था। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। मुसोलिनी अपने एक मात्र उद्देश्य की ओर, जो जनवाद को खत्म करना था, 1925 में बढ़ चला और विशाल नरसंहार से इसकी शुरूआत की। अपनी तानाशाही की जड़ों में उसने भयानकता के जाल को बुना था और उस व्यवस्था में उसने सारी जनता का पूर्ण समर्पण मांगा था। एक ऐसे देश का निर्माण करने के उद्देश्य को लेकर चला था जिसे उसने तानाशाही राज्य की संज्ञा दी थी।

यह 1925 का वर्ष हम भारतीयों के लिये भी ऐतिहासिक था, क्योंकि इसी साल, 27 सितंबर को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई थी और साथ ही इसी साल 26 दिसंबर को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना हुई थी। अक्टूबर 28 को मुसोलिनी ने ''फासीवादी क्रांति के दिवस'' के रूप में घोषित किया था। लेकिन यह क्रांति कभी पूरी नहीं हो पाई। इस सबसे पहले, 6 अप्रैल को इटालियन चुनाव में कम्युनिस्टों ने हिस्सा लेने का निर्णय लिया। लगातार भीषण फासीवादी आक्रमणों के बावजूद, उन्हें चुनाव में अच्छे वोट मिले, 2,68,000 मतों के साथ उन्होंने कई सीटों पर जीत भी हासिल की। जो विजयी हुए, उनमें एन्तोनियो ग्राम्शी का भी नाम था। वह बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे। 1920 के दशक में कई कठिन परिस्थितियां आई जिनमें माट्टीओट्टी नामक समाजवादी नेता की बर्बर हत्या भी थी। इटली कई विरोधाभासों में उलझ चुकी थी। फासीवाद विरोधी धाराएं मजबूत होती जा रही थीं, और तोगलियात्ती तथा ग्राम्शी जैसे कम्युनिस्ट नेता फासिज्म के विरूद्ध संयुक्त मोर्चे, (युनाइटेड फ्रंट) के समर्थन में खूब लिखने लगे थे। 1931 में इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी की चौथी कांग्रेस जर्मनी में आयोजित की गयी और इसमें तोगलियात्ती ने संयुक्त मोर्चे के समर्थन में तगड़ा नारा भी दिया। उन्हीं के प्रयासों से अगस्त 17, 1934 की मीटिंग में ट्रॉट्स्कीवादी, समाजवादी, कम्युनिस्ट और अतिक्रांतिवादी, भी शामिल हो गए और एक समझौते पर पहुंच गए। इसके बाद जल्दी ही कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की सातवीं कांग्रेस 1935 में हुई जिसमें इटली के कम्युनिस्ट नेता तोगलियात्ती ने एक बार फिर से संयुक्त मोर्चे की बात रखी। ज्यॉर्जी दिमित्रोव ने विभिन्न देशों, वर्गो को फासीवाद पर विजय पाने के लिये एकजुट होने का प्रस्ताव दिया। इन्हीं दिनों तोगलियात्ती ने अपने प्रसिद्ध लेख ''फासीवाद की शक्ति का स्रोत कहां है?'' में लिखा कि फासीवाद के सही रूप को समझना बहुत आवश्यक है। उन्होंने अर्थहीन मंतव्यों से और रुझानों से भी बचने के लिये आगाह किया। साथ ही उन्होंने इटालियन फासीवाद की धारणा को अन्य देशों के परिवेश में भी यांत्रिक रूप से लागू करने से भी सावधान किया। उन्होंने कहा कि जो कुछ इटली के लिये सही है, जरूरी नहीं कि अन्य देशों में भी वह सारा का सारा उसी तरह उपयोगी हो। अपने भाषणों में उन्होंने फासीवाद के उद्भव, इसकी रूपरेखा का विस्तार और वर्ग चरित्र, और साथ ही इटली के फासीवाद से जर्मनी के नाजीवाद का फर्क विस्तृत रूप से समझाया। यह किसी भी तरह से पूंजीवादी जनवाद का विकसित रूप नहीं है। अपनी सीमाओं के बावजूद जनवाद कभी भी फासीवाद का रूप नहीं हो सकता। फासीवादी शक्तियां जनवादी तरीके से बिल्कुल ही काम नहीं करतीं। फासीवाद तो जनवाद के समान जन समर्थन पर खड़ा नहीं रहता, न ही इसका चरित्र मैत्रीपूर्ण होता है। यह तो अन्यायपूर्ण तरीके से जनता पर बोझ डालता है और दासता को मजबूर करता है।

तोगलियात्ती ने फासीवाद की परिभाषा देते हुए कहा कि यह निरंकुश तत्वों की आतंकवादी तानाशाही है, जो साम्राज्यवादी, प्रतिकियावादी स्वरूप में वित्तपूंजी को सामने लाती है। मोनोपोली पूंजी की वृद्धि के लिये यह लोकप्रिय भूमि तैयार करने का काम करता है।

तोगलियात्ती और अन्य कम्युनिस्टों ने तेरहवीं प्लेनम में जोर दिया कि फासीवाद अपनी बुनियाद, आम साधारण स्तर के ऑफिस कर्मचारी, अन्य सिविल सर्वेन्ट्स जो बाकी समाज से पूरी तरह कट जाने के कारण अपनी अस्मिता खो बैठते हैं, इनकी सहायता से भी मजबूत करता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय ही लेनिन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि साम्राज्यवादी और मोनोपोली पूंजीवादी, जनवाद के उन तत्वों से अपनी दूरी बना रहे थे जो फासीवादी विकास के क्रम में तैय्यार हुए थे, और अब उन पर आक्रमण भी कर रहे थे। वस्तुतः लेनिन ने कहा कि नई अर्थव्यवस्था का एक पक्ष है, मोनोपोली पूंजीवाद, जो राजनैतिक जनवादी व्यवस्था से प्रतिक्रियावादी बन जाता है। यह जनवाद में कम्पीटिशन से आजाद स्वरूप में राजनैतिक प्रतिक्रियावादी मोनोपाली आर्थिक व्यवस्था के साथ चलती है। लेनिन ने यह भी देखा कि मोनोपोली पूंजी का एक प्रकृतिगत रुझान है कि वह जनवाद पर आक्रमण करता है, और एक खुली तानाशाही सत्ता लाने की कोशिश करता है। लेकिन यह भी सच है कि लेनिन हमेशा जनवाद की सीमित भूमिका की आलोचना करते रहे और समाजवाद जनवाद का समर्थन करते रहे। लेकिन वे हमेशा पूंजीवाद में जनवाद को बचाने की भी कोशिश करते रहे और बताते भी रहे है कि पूंजीवाद में जनवाद को कैसे बचाना है?

दशकों बीत जाने पर भी यह तथ्य अब तक उपयोगी हैं, लागू भी होते रहे हैं। इसका एक उज्ज्वल उदाहरण भारत अपने आपमें है। यह वित्तपूंजी का अर्थव्यवस्था पर शासन चलाता है। शोषण का स्तर अत्यंत अमानवीय स्तरों तक चला गया हैं। फासीवाद ने कारपोरेट राज्य की धारणा स्थापित करने की कोशिश की है, पर यह स्वयं भयानक रूप से अन्तर्विरोधों से घिर चुका है। संसद एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहां जनता का प्रतिनिधित्व स्पष्ट हुआ करता था, पर फासीवाद ने इस मंच को अपने प्रथम टारगेट्स में रखा है। जनता, भयानक बंदिशों और कानूनों से घिरी, अब यह सारा कुछ घसीटकर आगे बढ़ने के काबिल नहीं रही। लेकिन इतनी असहय, यातनामयी परिस्थितियों में भी, उनकी उम्मीदें बची हुई हैं।

मुसोलिनी को भी एक दिन अपनी जनता का सामना करना पड़ा था, और वही दंड झेलने पड़े थे जो उसने अन्यों को दिया था।

भाकपा विधायक दल के पूर्व नेता राजकुमार पूर्वे की 25वीं पुण्यतिथि

पटना, 9 अक्टूबर 2022: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक दल के पूर्व नेता स्वतंत्रता सेनानी कामरेड राजकुमार पूर्वे की 25वीं पुण्यतिथि रविवार को जनशक्ति भवन में मनाई गई।

पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय सहित पार्टी के दर्जनों नेता और कार्यकर्त्ताओं ने कामरेड राजकुमार पूर्वे की पुण्यतिथि मनाई। राज्य सचिव ने कहा कि कामरेड पूर्वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में छात्र जीवन में ही कूद पड़े थे। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरूआत एआईएसएफ से की थी। फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हो गए। पुराने दरभंगा जिले में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में उनकी महती भूमिका रही है। उनके नेतृत्व में कई भूमि आंदोलन सफल हुए। उन्होंने कहा कि कामरेड पूर्वे मधुबनी जिले के बिस्फी विधानसभा सीट से भाकपा के चार बार विधायक और एक बार बिधान पार्षद भी रहे। वे विधानसभा में पार्टी विधायक दल के नेता भी रहे। जीवन पर्यन्त छात्र, नौजवानों, किसानों, मजदूरों, शोषित पीड़ितों के लिए संघर्ष करते रहे। वे एक बहुत ही लड़ाकू साथी थे।

भाकपा राज्य सचिव कहा कि कामरेड राजकुमार पूर्वे ने अंग्रेजों से देश को आजाद कराने में महती भूमिका का निर्वहन किया। आजादी के बाद सामंती ताकतों से पूरी जिंदगी लड़ते रहे। वे किसान–मजदूरों के चहेते थे। अंग्रेजों ने जब उन्हे जेल में बंद कर दिया तो वे जेल की दीवार फांदकर बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता से भाजपा को हटाना ही कामरेड राजकुमार पूर्वे के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राजकुमार पूर्वे कहा करते थे कि राष्ट्रीय आंदोलन मुझे राजनीति में लाया और सामाजिक अत्याचार ने कम्युनिस्ट बनाया।

भाकपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जानकी पासवान, बाल किशोर मंडल, सुमंत जी, सिद्धेश्वर राम, अर्जुन राम, इंदु भूषण वर्मा, सुधीर कुमार, रमाकांत अकेला, पटना हाईकोट के वरीय अधिवक्ता योगेशचंद्र वर्मा, अधिवक्ता रामजीवन सिंह इत्यादि ने कामरेड पूर्वे जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की।

एमएसपी नाकाफी–प्रधानमंत्री इसे वापस लें–एआईकेएस

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कल प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक ने घोषणा करते हुए किसानों के साथ न्याय नहीं किया है। सर्दियों में बोई जाने वाली फसलों की कीमतों में तथाकथित वृद्धि लगातार बढ़ते कृषि इनपुट कीमतों की तुलना में मूंगफली की कीमत की पेशकश की तरह है। देश में सर्वाधिक रकबे में बोई जाने वाली फसल गेहूँ में 2022–23 की कीमतों की तुलना में केवल 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) के राष्ट्रीय महासचिव अतुल कुमार अनजान ने कहा कि कृषि इनपुट लागत 35 से 50 प्रतिशत तक बढ़ गई है। बढ़ते बिजली शुल्क, डीजल की कीमतें, बीज की लागत, उर्वरक, कीटनाशक की कीमतें किसानों की अर्थव्यवस्था और समग्र रूप से कृषि क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव दिखा रही हैं जो उत्पादन और उत्पादकता के लिए एक गंभीर खतरा बन सकती हैं।

डॉ. स्वामीनाथन समिति (राष्ट्रीय किसान आयोग) के पूर्व सदस्य अतुल कुमार अनजान ने कहा कि आयोग की सिफारिशों ने सी 2प्लस50 पर जोर दिया है, जबकि कृषि उपज की लागत का निर्धारण सीसीईए द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए प्रधानमंत्री की घोषणा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना एक नारा बनकर रह गया है।

अखिल भारतीय किसान सभा मांग करती है कि केन्द्र सरकार सीसीईए के द्वारा घोषित पूरी एएमएसपी की समीक्षा करे और इसे वापस लेकर इसका निर्धारण सी2प्लस50 तरीके से किया जाये।

एक पूर्व साम्राज्यवादी का आर्थिक संघर्ष

श्रीनिवास खान्डेवाले

ग्रेट ब्रिटेन इस समय आर्थिक उथल–पुथल के दौर से गुजर रहा है। एक तरह से सभी देश पिछले दो वर्षो (2020–21, 2021–22) से महामारी के प्रतिकूल आर्थिक प्रभावों का सामना कर रहे हैं और रिकवरी की राह पर हैं। गेहूं की आपूर्ति, तेल और गैस की आपूर्ति में कमी के मामले में ब्रिटेन और यूरोप रूस–यूक्रेन युद्ध के प्रभाव से पीड़ित हैं। इसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन में उच्च मुद्रास्फीति (लगभग 10 प्रतिशत) हुई है। इसे 40 साल में सबसे ज्यादा माना जा रहा है। इससे कारोबारियों में अस्थिरता और बढ़ गई है। 45 दिनों की अवधि के भीतर, दो प्रधानमंत्रियों को सत्तारूढ़ रूढ़िवादी पार्टी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है और इसके दूसरे, तीसरे प्रधान मंत्री ऋषि सुनक (भारतीय मूल के) को 24 अक्टूबर 2022 को सदन के नेता के रूप में चुना गया है। जो आर्थिक उतार–चढ़ाव और उनके राजनीतिक परिणाम हुए हैं, उसने दुनिया को हैरान और झकझोर कर रख दिया है।

ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के सामने मुख्य आर्थिक चुनौतियां हैः ऐतिहासिक रूप से उच्च मुद्रास्फीति, निरंतर मुद्रास्फीति ने गिल्ट–एज सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य को कम कर दिया है, कम मूल्य के कारण उनकी कीमतों में गिरावट आई है। ये प्रतिभूतियां कर्मचारी पेंशन निधि की मुख्य परिसंपत्ति (निवेश) रही हैं। ये फंड एक तरफ बाजार में निवेश योग्य फंड का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं और दूसरी ओर श्रमिकों की बचत के लिए स्थिर रिटर्न। मुद्रास्फीति ने आम आदमी के इस आय स्रोत को और ब्रिटिश निवेश बाजार में पेंशन फंड की हिस्सेदारी को भी गिरा दिया है। रूस (जिस पर यूरोप और ब्रिटेन बहुत अधिक निर्भर हैं) से गैस और तेल की आपूर्ति में भारी कमी ने एक लंबी और भीषण सर्दी के समय में ऊर्जा का संकट पैदा कर दिया है। ऊर्जा राशनिंग पर विचार किया जा रहा है और तेजी से बढ़ती ऊर्जा की कीमतों को अब जीवन की लागत का संकट कहा जा रहा है। यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' की रिपोर्ट ने भी इसके शीर्षक में 'काउंटरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस' एक बाई लाइन जोड़ दी है। हालांकि भारत की तुलना में उच्च स्तर पर परिचालन, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था एक नए आर्थिक संकट का सामना कर रही है। 2008 में अमेरिकी सब–प्राइम लेंडिंग संकट के कारण हुई दुर्घटना से बाहर आने के बाद, यूके अब महामारी के बाद के प्रभावों का सामना कर रहा है, रूस–यूक्रेन युद्ध के प्रत्यक्ष परिणाम और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के आवधिक परिणाम, जैसे कम आय और जनता की आजीविका क्रय शक्ति में गिरावट, ब्याज की बढ़ती दरें रोजगार सृजन आदि को प्रभावित कर रही हैं।

कन्जर्वेटिव नीतियां

कंजर्वेटिव पार्टी ने अपनी अल्पकालिक सरकारों के माध्यम से, अपनी रूढ़िवादी अमीर समर्थक, मजदूर विरोधी नीतियों को लगाने की कोशिश की, जिसने मजदूर वर्ग और पूंजी बाजार पर भी अचानक हमले शुरू कर दिए हैं। आर्थिक सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने आम लोगों को कोई सहायता देने से परहेज किया लेकिन सुपर अमीरों को कर में कटौती की पेशकश की और राजस्व हानि को पब्लिक के धन से पूरा करने का प्रस्ताव दिया गया। चूंकि धारणा यह है कि सरकार के पास अतिरिक्त ऋण चुकाने की क्षमता नहीं है, जिस पर बाजार और लोगों ने अचानक और तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पिछले प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को 'वास्तविक गलती' के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। प्रमुख उद्योगों में से ट्रेड यूनियनें पहले ही जा चुकी हैं और कुछ ने हड़ताल पर जाने का नोटिस जारी कर दिया है। कुल मिलाकर पूरा मामला जनविरोधी हो गया है।

नवनिर्वाचित प्रधान मंत्री, ऋषि सुनक, बहुत पहले के अपने भारतीय मूल के और भारत में अपने वर्तमान विवाह संबंध के बावजूद, एक जन्मजात ब्रिटिश, ब्रिटिश उच्च शिक्षित, इंग्लैंड के वर्तमान राजा से अधिक अमीर, एक ब्रिटिश नागरिक हैं, जिन्हें रूढ़िवादी आर्थिक विचारों वाली कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने उनके पार्टी के दृष्टिकोण के तहत राष्ट्रीय संकट को हल करने के लिए एक जनादेश के साथ चुना गया है। ये सभी कारक, वास्तव में, नए पीएम से हमारी उम्मीदों को कम करते हैं। मुख्य रूप से चिलींग प्वाइंट 2022 और 2023 की सर्दियों के दौरान ऊर्जा–आपातकाल हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक–2022 ने पहले ही चेतावनी दी है कि '... सबसे बुरा अभी आना बाकी है', यह आगे सूचित करता है कि 'हमारे नवीनतम पूर्वानुमान वैश्विक विकास को प्रोजेक्ट करते हैं विकास 2022 में 3.2 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेगा और 2023 में 2.7 प्रतिशत तक कम होगा ... इसकी 25 प्रतिशत संभावना है कि यह 2 प्रतिशत से नीचे गिर सकता है ... कई लोगों के लिए, 2023 मंदी की तरह महसूस करेगा (वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022, आईएमएफ , पी.गपपप) बहुत से कम आय वाले देश ऋण संकट में हैं या उसके करीब हैं ... संप्रभु ऋण संकट की लहर को रोकने के लिए सबसे अधिक प्रभावित देशों के लिए सामान्य ढांचे की तत्काल आवश्यकता है। समय जल्द ही समाप्त हो सकता है।' (ओपी. सीआईटी. पी. 14)

साम्राज्यवादी कारक

एक गहन विचार से एक प्रश्न उठेगा कि ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली साम्राज्यवादी देश को मुद्रास्फीति जारी रहने की स्थिति में आर्थिक अस्थिरता, बेरोजगारी, कम मजदूरी का क्यों सामना करना चाहिए? एक कारण जो प्रशंसनीय प्रतीत होता है वह यह है कि जैसा कि दस्तावेजी साक्ष्य से पता चलता है, पहले उपनिवेशों को सदमा बर्दाश्त (कम मजदूरी, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, गरीबी आदि के लिए) करने वाले के रूप में माना जाता था और लाभ साम्राज्यशाही देश को जाता था। साम्राज्यशाही देश के भीतर भी अमीर लोगों को लाभ हुआ और ब्रिटेन में आम लोगों ने बेहतर पारिश्रमिक के लिए (मुख्य रूप से यू.एस.) पलायन किया। इसका मतलब है कि ब्रिटेन का पूंजीवाद, अपने अब तक के सबसे बड़े साम्राज्य (लगभग 40 उपनिवेश देशों के साथ) के साथ, या तो अधीन लोगों को या अपने स्वयं के नागरिकों को भी आर्थिक न्याय नहीं दे सका। लेकिन क्रॉस लेनदेन से, साम्राज्य (और अन्य छोटे साम्राज्यों) ने स्थिरता का अनुभव किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, साम्राज्य का समापन हो गया, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था एक छोटे से देश की हो गई, जो अपनी सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक समस्याओं को हल करने में असमर्थ थी, जैसे कि यूरोपीय आम बाजार में रहना है, अपने संचित धन को कैसे चुकाना है। सार्वजनिक ऋण, अपने पूर्व साम्राज्य से संबंधित लोगों के वीजा–आगमन को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसकी अर्थव्यवस्था को कैसे स्थिरता प्रदान की जाए, अब एक कठोर अर्थव्यवस्था में आय असमानताओं को कैसे नियंत्रित किया जाए, 2024 में आम चुनाव का सामना करने जा रही कंजरवेटिव पार्टी के लिए जनता का वोट कैसे प्राप्त करें, आदि।

इससे भी अधिक हैरान करने वाला प्रश्न यह है कि साम्राज्यशाही युग के दौरान, साम्राज्य के विस्तार और प्रबंधन के लिए, यूके में नए राजनीतिक विचार, सिद्धांत सामने आए, लेकिन साम्राज्य को खोने के बाद, यूके में नवीन शक्ति में गिरावट आई है। पॉल कोलियर, ऑक्सफोर्ड ब्लावाल्निक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में अर्थशास्त्र और सार्वजनिक नीति के प्रोफेसर, गहन टिप्पणी (द फ्यूचर ऑफ कैपिटलिज्मः फेसिंग द न्यू एंग्जाइटी, एलन लेन, 2018, पृष्ठ 201) कि 'पूंजीवाद विभाजित समाज पैदा कर रहा है जिसमें कई लोग हैं चिंतित जीवन जीते हैं। महामंदी के बाद के युग के दौरान, व्यावहारिक नीतियों ने पूंजीवाद को पटरी पर ला दिया, वे ऐसा फिर से कर सकते हैं। फिर भी हमारी राजनीतिक व्यवस्था ऐसी नीतियां नहीं बना रही है। यह हमारी अर्थव्यवस्थाओं की तरह ही बेकार हो गया है। यह अब समस्याओं के समाधान के बारे में व्यावहारिक रूप से सोचने में सक्षम क्यों नहीं है?

आइए प्रतीक्षा करें और देखें कि क्या प्रधानमंत्री सुनक ब्रिटिश व्यवस्था को बदलने में सक्षम हैं ताकि इसकी वर्तमान आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को हल किया जा सके?

भाकपा की एनी राजा के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की मांग

नई दिल्लीः भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिवमंडल ने 2 नवंबर 2022 को निम्नलिखित बयान जारी करते हुए भाकपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन (एनएफआईडब्ल्यू) की महासचिव एनी राजा के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने की मांग कीः

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय सचिवमंडल भाकपा की राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य और एनएफआईडब्ल्यू महासचिव एनी राजा के खिलाफ दर्ज मामले की निंदा करता है और इसे वापस लेने की मांग करता है।

उनके खिलाफ दर्ज मामला दिसंबर 2021 में समान नागरिकता के विरोध के दो साल होने पर जंतर मंतर आयोजित एक सार्वजनिक बैठक के संबंध में है। उस पर आईपीसी की धारा 144, महामारी रोग अधिनियम की धाराओं और आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप है। पार्टी को लगता है कि यह मामला पूरी तरह से निराधार है और इसका उद्देश्य भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध करने और विरोध की आवाज को दबाना है।

भाकपा सभी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक दलों और आंदोलनों से अपील करती है कि वे तत्कालीन सरकार की जनविरोधी नीतियों और नागरिकों के संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए असहमति की अभिव्यक्ति के बचाव में अपनी आवाज उठाएं।

एनी राजा आज 2 नवंबर 2022 को पटियाला हाउस कोर्ट में हुई एक सुनवाई में शामिल हुई और उन्हें जमानत दे दी गयी। पटियाला हाउस कोर्ट ने अगली सुनवाई 7 जनवरी 2023 को निर्धारित की है।

विभिन्न देशों की बिरादराना पार्टियों के बधाई संदेश

फिलीपीन्स की कम्युनिस्ट पार्टी का संदेश

फिलीपीन कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव की ओर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं कांग्रेस के लिए अभिनंदन संदेश

प्रिय साथियों,

द पर्तीदो काममुनिस्ता न्ग पीलिपिनास (पीकेपी– 1930, फिलीपीन कम्युनिस्ट पार्टी) साथीपन के साथ अपना हार्दिक अभिनंदन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं काँग्रेस के लिए प्रेषित करती है। पीकेपी – 1930 कार्पोरेट परस्त भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के दक्षिणपंथी शासन के सांप्रदायिक (हिन्दुत्व) कार्यक्रमों के खिलाफ और भाजपा जो कि भारत सरकार का संचालन करती है और जिनके कार्यक्रमों के कारण भारत आज गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकटों का सामना कर रहा है, इस भाजपा नीत सरकार के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संघर्ष का पूर्ण समर्थन करती है।

हम भारतीय समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने–बाने की रक्षा के लिए और धार्मिक आधार पर भाजपा द्वारा भारतीय समाज के ध्रुवीकरण के प्रतिरोध में एक व्यापक वामपंथी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष मोर्चा बनाने के भाकपा के कार्यक्रम की पूरी सफलता की कामना करते हैं।

हम इसके अलावा आपकी पार्टी की मजबूती के लिए आपकी 24वीं काँग्रेस द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों की सफलता की कामना करते हैं, ताकि भाजपा सरकार द्वारा अपनाई गई नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिक जन आंदोलन शुरू किया जा सके।

इस महत्वपूर्ण काँग्रेस में हमारी पार्टी की ओर से एक प्रतिनिधि भेजने के लिए आपकी पार्टी द्वारा आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और हम आपके निमंत्रण का सकारात्मक जवाब देने में अपनी असमर्थता पर खेद व्यक्त करते हैं। कृपया आश्वस्त रहें कि हम दोनों पार्टियों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और साम्राज्यवाद, नव–फासीवाद, नस्लवाद और साम्प्रदायिकता के खिलाफ हमारे साझा संघर्ष के प्रति और शांति, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और समाजवाद के लिए संघर्ष के प्रति हमारी स्थायी प्रतिबद्धता को गहरा महत्व देते हैं।

कम्युनिस्ट अभिनंदन के साथ

बेल्जियम की वर्कर्स पार्टी (पी टी बी पी वी डी ए) की ओर से अभिनंदन संदेश

प्रिय साथियों,

हम 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2022 तक आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं काँग्रेस में शामिल होने हेतु निमंत्रण के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। दुर्भाग्य से, इस अवधि में कम्युनिस्ट और वर्कर्स पार्टियों के कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों और हमारे अपने देश में सामाजिक संघर्ष में तेजी के कारण, बेल्जियम की वर्कर्स पार्टी के लिए आपकी पार्टी काँग्रेस के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजना संभव नहीं होगा।

हम भाकपा की 24वीं काँग्रेस की सफलता की कामना करते हैं। चर्चा होने के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति के संबंध में और पार्टी के संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण की चुनौतियों के बारे में लिए जाने वाले निर्णयों की सफलता की कामना करते हैं।

आपकी पार्टी काँग्रेस दुनियाभर में संचित गंभीर संकट के समय में हो रही है:, अमेरिकी साम्राज्यवाद और नाटो द्वारा समर्थित और लाभ उठाया। इन संकटों के साथ, विश्व पूंजीवादी प्रणाली के विरोधाभास अधिक तीव्र और स्पष्ट हो रहे हैं।

उक्रेन के युद्ध ने, जिसका अमरीकी साम्राज्यवाद और नाटो द्वारा समर्थन और लाभ उठाया गया, एक आर्थिक, वित्तीय, जलवायु और स्वास्थ्य संकट, को और अधिक बदतर खतरनाक बना दिया।

ये संकट चाहे जलवायु विपत्तियों, युद्ध, सामाजिक असमानताओं या साम्राज्यवाद की शक्तियों द्वारा वैश्विक दक्षिण के साथ किए गए अन्याय और कष्टों के कारण बड़े हों: कामगार वर्ग, मेहनतकश जनता और युवा अधिक सचेत हो रहे हैं कि उन्हें पूंजीवाद के बुनियादी विकल्प की तलाश करनी है।

कम्युनिस्ट और वर्कर्स पार्टियों के बतौर हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम मजदूर वर्ग और जनता के मौजूदा और आगामी संघर्षो में उम्मीद और दृष्टिकोण जोड़ें। पूंजीवादी व्यवस्था के कष्ट और युद्ध पर एकमात्र व्यवहार्य और टिकाऊ विकल्प के लिए हमें बहस को खोलने और व्यापक करने की जरूरत हैरू समाजवाद।

साम्राज्यवाद के खिलाफ हमारे साझे संघर्ष के लिए, शांति, लोकतंत्र और समाजवाद के लिए हमें अपने साझे संघर्ष के साथ आगे बढ़ना है।

कम्युनिस्ट अभिनंदन सहित

स्वाजीलैंड कम्युनिस्ट पार्टी का अभिनंदन संदेश

स्वाजजीलैंड की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएस) भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं काँग्रेस के प्रतिनिधियों को क्रांतिकारी बधाई देती है। सीपीएस आपकी पार्टी के नेतृत्व को भी बधाई देती है कि उन्होंने पार्टी को बरकरार रखा और इस काँग्रेस तक साहसपूर्वक नेतृत्व किया। सीपीएस अपने–अपने संघर्षो में जुटे भारत के समस्त मजदूर वर्ग और किसानों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करती है। सीपीएस भारत में वामपंथी ताकतों को एकजुट करने के उन सभी प्रयासों का भी समर्थन करती है, जिसमें विशेष रूप से कम्युनिस्ट आंदोलन शामिल हैं।

सीपीएस के रूप में, हम स्वाजीलैंड में स्वतंत्रता के संघर्ष में हम अग्रणी पंक्ति में हैं। स्वाजीलैंड के लोग 12 अप्रैल 1973 को आधिकारिक रूप से स्थापित पूर्ण राजशाही की यातनाओं से उस समय से परेशान हैं, जब सम्राट ने 1968 के स्वतंत्रता संविधान को एकतरफा रूप से निरस्त कर दिया, सभी राजनीतिक दलों और गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया, और सभी विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां स्वयं को प्रदान की। सीपीएस ने स्वाजीलैंड में राजनीतिक दलों के बहिष्कार और लोकतंत्र में बदलाव के लिए संघर्ष के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का आह्वान किया।

सीपीएस हमारे दोनों पक्षों के बीच घनिष्ठ संबंधों का आह्वान करता है, ताकि शांति, लोकतंत्र और समाजवाद के लिए साम्राज्यवाद के खिलाफ हमारे साझा संघर्ष को मजबूत किया जा सके।

कम्युनिस्ट अभिनंदन सहित

पुर्तगाली कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से अभिनंदन संदेश

पुर्तगाली कम्युनिस्ट पार्टी अपार हर्ष के साथ आपके माध्यम से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं काँग्रेस के सभी पार्टी प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन करती है और आपके माध्यम से आपके विशाल देश के सभी भारतीय कम्युनिस्टों और वर्कर्स और जनता का अभिनंदन करती है।

हम आपकी काँग्रेस की कार्यवाहियों की सफलता के लिए शुभ कामनाएं देते हैं, आश्वस्त हैं कि काँग्रेस के निर्णयों से आपकी पार्टी को और वर्कर्स की और भारत की जनता को अधिकारों के लिए संघर्ष को और आकांक्षाओं मजबूती मिलेगी।

साथियों, दुनिया के वर्कर और जनता बहुत ही गंभीर और खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का सामना कर रही है।

पूंजीवाद अपनी शोषक, उत्पीड़क, आक्रामक और भक्षक प्रकृति को उद्घाटित करता है, जो कि अधिकारों की और लाखों इंसानों की बुनियादी जरूरतों की अस्वीकृति के द्वारा, स्वतंत्रता और जनतंत्र पर हमलों के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय तनावों के बढ़ने के द्वारा युद्ध को बढ़ावा देने द्वारा, पर्यावरणीय समस्याओं के बिगड़ने द्वारा भयावह रूप से व्यक्त होते हैं।

पूंजीवाद के संरचनात्मक संकट के गहराने के साथ बड़ी पूंजी शोषण को, अधिकारों पर हमलों को, संपदा के केन्द्रीयकरण और जमाव के बढ़ने को, अपने वर्ग दबदबे को सघन करती है।

साथ ही साथ, संयुक्त राज्य अमरीका, अपने मातहतों को, खासतौर से नाटो और यूरोपीय संघ को अपने पक्ष में खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं, वैश्विक वर्चस्व प्रभुत्व को लादने की अपनी रणनीति को सघन कर रहे हैं, धमकियों, भेद खोलने की धमकी, प्रतिबंधों, नाकाबंदी की अपनी नीतियों को चला रहे हैं।

जैसे कि एशिया–प्रशांत क्षेत्र में सैन्यकरण को फैलाने के उद्देश्य से एयूकेयूएस या क्वाड, दूसरे गठबंधनों और साझीदारियों के अलावा, निरंतर–विस्तारशील नाटो को, विश्व प्रभुत्व की रणनीति की सेवा में एक विश्व यंत्र में रूपांतरित कर दिया गया था।

दुनिया की प्रगतिशील सरकारों और ताकतों के साथ–साथ उन सभी देशों को भी को निशाना बना रहे हैं, जो अपनी सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं की परवाह किए बिना अमेरिका द्वारा निर्धारित दुनिया को स्वीकार नहीं करते, वर्तमान स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाती है कि साम्राज्यवाद राष्ट्रों के संप्रभु विकास को उनके स्वयं के विकास के रास्ते को तय करने का अधिकार को, राष्ट्रीय संसाधनों के संप्रभु उपयोग के अधिकार को और एक स्वतंत्र विदेश नीति के अधिकार को रोकने की कोशिश करता है।

संयुक्त राज्य अमरीका, अन्य जी–7 प्रमुख पूंजीवादी शक्तियों के साथ, अपनी सापेक्ष गिरावट का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, जो विश्व स्तर पर होने वाली शक्तियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने और उलटने की कोशिश कर रहा है, जो निष्पक्ष रूप से साम्राज्यवाद के वर्चस्ववादी शासन को चुनौती देता है।

इस संदर्भ में साम्राज्यवाद यूक्रेन को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए युद्ध को खतरनाक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करते हुए रूस के खिलाफ संघर्ष करता है जबकि साथ ही साथ चीन, को अपना प्रमुख निशाना मानते हुए इसके विरुद्ध अपनी संघर्ष की नीति को तेज करता है।

साम्राज्यवाद द्वारा टकराव में तेजी युद्ध को फैलाने की धमकी देता है और दुनिया को तबाही की ओर ले जा सकता है।

साथियों, यह गंभीर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति उन लोगों के साथ एकजुटता विकसित करने की मांग करती है जो साम्राज्यवाद के विरोध और शांति के लिए संघर्ष में, फासीवाद और युद्ध के खिलाफ संघर्ष में, साम्राज्यवाद द्वारा टकराव बढ़ने के खिलाफ, नाटो के विस्तार के खिलाफ और इसके विघटन के लिए हैं।

खतरों के बारे में, लेकिन श्रमिकों और लोगों के संघर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की संभावनाओं के बारे में भी जानते हुए, पुर्तगाली कम्युनिस्टों ने अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट और क्रांतिकारी आंदोलन और एक व्यापक साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चा को मजबूत करने के लिए विश्वासपूर्वक प्रतिबद्धता व्यक्त की है जो साम्राज्यवाद द्वारा रसातल की ओर होड़ को रोक सकता है और यह सभी इंसानों के लिए शांति और सामाजिक प्रगति के भविष्य को सुनिश्चित कर सकता है।

साथियों, पुर्तगाली कम्युनिस्ट पार्टी शांति के लिए संघर्ष में पुर्तगाली कार्यकर्ताओं और लोगों को एकजुट करने के लिए पूरी ताकत के साथ प्रतिबद्ध है, जीवन यापन के बढ़ते खर्चे और कई अन्य बहानों से हमले मजदूरों के और उनके दूसरे सामाजिक अधिकारों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं।

पुर्तगाल में हम इस विश्वास के साथ हैं कि, हम दक्षिणपंथी नीति के खिलाफ संघर्ष जारी रखे हुए हैं, एक देशभक्त और वामपंथी विकल्प के लिए, 1974 की, अप्रैल क्रांति के मूल्यों के साथ एक उन्नत लोकतंत्र के लिए, जो हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए समाजवाद के लिए एक संघर्ष में निहित है, पुर्तगाली मजदूरों और जनता के साथ इसके संबंध, ताकि वह अपने राष्ट्रीय कामों, अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों, अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को पूरा कर सके।

साथियों, सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप में समाजवादी खेमे के विघटन के बाद मजदूरों और जनता द्वारा अपने सामाजिक और राष्ट्रीय मुक्ति के संघर्ष में हासिल की गई उपलब्धियों और प्रगति के खिलाफ साम्राज्यवाद द्वारा हिंसक कार्रवाई की शुरुआत की गई।

लेकिन पूंजीवाद इतिहास का अंत नहीं है। प्रगतिशील और क्रांतिकारी परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए अधिक सामान्य संघर्ष के साथ अल्पकालिक लक्ष्यों के संघर्ष को चलाना, समाजवाद लोगों के भविष्य की संभावना है।

हमारी दोनों पार्टियों के बीच मैत्री और एकजुटता के मेलभाव की पुष्टि करते हुए और उन्हें मजबूत करने की इच्छा व्यक्त करते हुए, हम एक सफल 24वीं काँग्रेस की कामना करते हैं जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय मजदूरों और जनता, और दुनिया भर के मजदूरों और लोगों के हितों और आकांक्षाओं की रक्षा में इसके संघर्ष को मजबूत करने में योगदान देगी।

पुर्तगाली कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मैत्री जिन्दाबाद!

सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद जिन्दाबाद!

अन्तर्राष्ट्रीयवादी एकजुटता जिन्दाबाद!

कम्युनिस्ट नेताओं की जीवनी–76

आरपीडी: भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के मार्गदर्शक

अनिल राजिमवाले

रजनी पाम दत्त जो इतिहास में 'आरपीडी' के नाम से सुप्रसिद्ध हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन (सी. पी.जी.बी.) के जाने–माने नेता और सिद्धांतकार थे। हालांकि वे कभी भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं रहे फिर भी उनका नाम भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ अविभाज्य रूप से संबंधित है। उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन की समय–समय पर सहायता की तथा मार्ग निर्देशन किया और एक सैद्धांतिक शिक्षक के रूप में काम किया। उनकी सुप्रसिद्ध किताब 'इंडिया टुडे' या आज का भारत कम्युनिस्टों, क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक का काम करती रही है।

आरंभिक जीवन

आरपीडी का जन्म 19 जून 1896 को इंग्लैंड में कैंब्रिज के मिल रोड में हुआ था। उनके पिता डाक्टर उपेंद्र कृष्ण दत्त थे जो भारतीय सर्जन थे लेकिन ब्रिटेन में ही बस गए थे। महान भारतीय विद्वान और देशभक्त रोमेश चंद्र दत्त के आर पी डी भतीजे थे। उनकी माता का नाम अन्ना पाम था और वे स्वीडिश महिला थीं। स्वीडन के प्रधानमंत्री ओलोफ पाम की वे पर–चाची थीं। आरपीडी के बहन का नाम था एलना पाम दत्त था जो जेनेवा स्थित आईएलओ में एक अफसर के पद पर थीं। आरपीडी के बड़े भाई क्लीमेन्स पाम दत्त इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता थे।

डा. उपेंद्र कृष्ण दत्त का भारतीयों से गहरा संबंध था और उनके घर में भारतीय विद्यार्थियों की मीटिंगें हुआ करतीं। मजलिस नामक भारतीय विद्यार्थियों के संगठन की बैठकें उन्हीं के घर में आयोजित की जाती। आरपीडी याद करते हैं कि इन बैठकों में जवाहरलाल नेहरू भी आया करते। आरपीडी की पढ़ाई कैंब्रिज के पेरसे स्कूल में और आक्सफोर्ड के बेलीओल कालेज में हुई थी। उन्हें 1916 में प्रथम विश्व युद्ध का विरोध करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि सभी नौजवानों को सेना में भर्ती होना अनिवार्य था। वे शिक्षा में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए और उन्हें क्लासिक्स, दर्शन और इतिहास में आनर्स मिला। कालेज में पढ़ते हुए उन्होंने रूसी क्रांति के समर्थन में सभा का आयोजन किया जिस के जुर्म में उन्हें सस्पेंड किया गया। कुछ समय बाद उन्हें फिर भर्ती कर लिया गया और उन्होंने परीक्षा में बड़ा अच्छा किया। सुप्रसिद्ध विद्वान एंड्रु रोथश्टेन कहते हैं कि आरपीडी सोशल डेमोक्रेटिक फेडरेशन की बैठकों में भाग लिया करते।

कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने लार्ड कर्जन को 21 मार्च 1919 को लिखा कि कैंपस में कुछ खतरनाक तत्व मौजूद हैं जैसे क्लीमेंस दत्त और रजनी पाम दत्त।

आरपीडी का विवाह 1922 में सलमे मुरुक के साथ हुआ जो एस्टोनिया की रहने वाली थी। वे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की प्रतिनिधि बनकर ब्रिटेन आई हुई थी।

आई एल पी में

आरपीडी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी में तभी शामिल हो गए जब वे अभी अपनी पढ़ाई ही कर रहे थे। वे पार्टी के रिसर्च डिपार्टमेंट में इसके इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के सचिव के रूप में 1919 से काम करने लगे। उन्होंने 1921 में लेबर इंटरनेशनल हैंडबुक का संपादन किया। आरपीडी ने पार्टी के अंदर शापूर्जी सकलतवाला के साथ मिलकर कम्युनिज्म का प्रचार किया और स्नोडेन तथा मैकडनल्ड के दक्षिण पंथ का विरोध किया।

आरपीडी, सकलतवाला, वाल्टन न्यू बोल्ड, और एमिली बर्न्स ने मिलकर पार्टी के अंदर एक समिति का गठन किया जिसका काम था तीसरी इंटरनेशनल के साथ संबद्धता का प्रचार करना। उन्होंने एक बुलेटिन भी प्रकाशित करना शुरू किया जिसका शीर्षक था द इंटरनेशनल।

सीपीजीबी में

यह ग्रुप औपचारिक रूप से 1921 की जनवरी में सीपीजीबी में उसकी स्थापना के तुरंत बाद ही शामिल हो गया। बाद में आर पी डी ने पार्टी की पत्रिका 'लेबर मंथली' का संपादन शुरू किया जो अपनी मृत्यु तक करते रहे। आगे चलकर उन्होंने पार्टी अखबार **डेली वर्कर** का भी

संपादन किया और साथ ही 1922 में **वर्कर्स वीकली** का संपादन भी आरंभ किया। उनकी देखरेख में अखबार का सरकुलेशन 8000 से बढ़कर 50000 तक पहुंच गया।

आरपीडी सीपीजीबी की कार्यकारिणी में चुने गए और 1965 का इसके सदस्य बने रहे। वे पार्टी की पोलित ब्यूरो में भी चुने गए। वे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की कार्यकारिणी के सदस्य बनाए गए और उसकी प्रेसीडियम के वैकल्पिक सदस्य भी बने।

आरपीडी कई वर्षो तक बेल्जियम तथा स्वीडन में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधि की हैसियत से काम करते रहे।

1937 में विभिन्न विद्वानों को लेकर एक संयुक्त मोर्चा समिति का गठन किया गया जिसके सदस्य थे आरपीडी, स्टैफोर्ड क्रिप्प्स, माइकल बेवन, हैरी पोलित, फेनर ब्रोकवे और मैक्सटन।

आरपीडी और भारत

इस एस ए डांगे 1974 में लिखते हैं कि 'आरपीडीए', ये तीन अक्षर मजदूर आंदोलन के संपूर्ण इतिहास को दर्शाते हैं। पूरे 54 वर्षो तक इन अक्षरों की छत्रछाया में ग्रेट ब्रिटेन, भारत और अंग्रेजी जानने वाले देशों में मजदूर और कम्युनिस्ट आंदोलन फलता फूलता रहा और उनके लेखों एवं

रचनाओं से स्फूर्ति ग्रहण करता रहा। वे नियमित रूप से **लेबर मंथली** में 'नोट्स ऑफ द मंथ' लिखते रहे। वे इनमें विश्व अर्थतंत्र तथा राजनीति का गहन विश्लेषण करते रहे।

माडर्न इंडिया और इंडिया टुडे जैसी उनकी रचनाएं आधुनिक भारतीय इतिहास की क्लासिकल रचनाएं मानी जाती है। उन्होंने **फासिज्म एंड सोशल रिवोल्यूशन, वर्ल्ड पालिटिक्स 1918 से 1936,** ब्रिटिश साम्राज्य संबंधी रचनाओं के जरिये पूंजीवादी संकट एवं फासिज्म का विश्लेषण किया।

वे भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन से अभिन्न रूप से जुड़े हुए थे और उन्हें ग्रेट ब्रिटेन स्थित भारतीय कम्युनिस्ट माना जाता था।

सीपीजीबी के चार्ल्स एशले 19 सितंबर 1921 को बम्बई पहुंचे और पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वे गुप्त रूप से निकल भागे और इस एस ए डांगे से मिले। उनकी मुलाकात बाम्बे क्रानिकल नामक अखबार के दफ्तर में हुई।

ऐशले ने डांगे को आरपीडी और सीपीजीबी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। डांगे द्वारा प्रकाशित **द सोशलिस्ट** अखबार आरपीडी के **लेबर मंथली** अखबार के साथ संपर्क में था। इसके अलावा उसका संपर्क **वर्कर्स ड्रेडनाट** के साथ भी था जिसका प्रकाशन सिलविया पैंकहर्स्ट कर रही थीं।

डांगे तथा अन्य कम्युनिस्टों ने आरपीडी द्वारा **एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका** में प्रकाशित और उनके द्वारा लिखित **कम्युनिज्म** संबंधी नोट को पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया और उसे दो आने मूल्य पर बेचा। इसका विज्ञापन 18 नवंबर 22 को **द सोशलिस्ट** में प्रकाशित हुआ

।आरपीडी द्वारा रचित **मॉडर्न इंडिया** 1926 में मुंबई में प्रकाशित किया गया।

आरपीडी तथा सीपीजीबी ने मेरठ षड्यंत्र मुकदमे के कैदियों की रक्षा में समिति का गठन किया जिसने उनके समर्थन में अभियान चलाया और धन इकट्ठा किया।

भारतीय विद्यार्थियों पर प्रभाव

(भारतीय विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों की) कई पीढ़ियां आरपीडी और सीपीजीबी से प्रभावित हुई। सीपीजीबी का औपनिवेशिक विभाग सक्रियता से भारत की आजादी के आंदोलन के पक्ष में प्रचार कर रहा था।

जो हस्तियां उनसे प्रभावित हुई उनमे शामिल थे–

जवाहरलाल नेहरू, वीके कृष्ण मेनन, इंदिरा गांधी, डीआर गाडगिल, सुशोभन सरकार, के वी गोपालास्वामी, बाकर अली मिर्जा, निहारेंदु दत्त मजुमदार, मोहित सेन, ज्योति बसु, इंद्रजीत गुप्ता, पी एन हक्सर, एन के कृष्णन, रेणु चक्रवर्ती, प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, दिलीप बोस, पार्वती कृष्णन, भूपेश गुप्ता, हाजरा बेगम, सज्जाद जहीर तथा कई अन्य। उनमें से बहुत सारे लोग आगे चलकर कम्युनिस्ट बन गए। उनकी राजनीतिक क्लासें सीपीजीबी के नेता लिया करते जिनमें आरपीडी भी शामिल थे।

दत्त ब्रेडले थीसिस, 1936

यह थीसिस आरपीडी और बेन ब्रैडले ने उस वक्त लिखा था जब फासिज्म और युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा था। थीसिस ने साम्राज्यवाद विरोधी संयुक्त मोर्चे के गठन का उद्देश्य पेश किया। इस मोर्चे में राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग भी शामिल था। इसके अलावा थीसिस में मजदूरों और किसानों के संगठनो को कांग्रेस के साथ सम्बद्ध करने का प्रस्ताव भी पेश किया गया। इस थीसिस ने संयुक्त मोर्चा की रणनीति और कार्यनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

लेनिन की मृत्यु कि तुरंत बाद ही कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने उनकी औपनिवेशिक थीसिस त्याग दी और साथ ही संयुक्त मोर्चा की कार्यनीति भी। 1925 में स्तालिन ने यह घोषणा की कि 'राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग साम्राज्यवाद के खेमे में जा चुका है'। 1926 में उन्होंने कहाकि गांधीजी साम्राज्यवाद के एजेंट बन चुके हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की छठी कांग्रेस का कार्यक्रम पूरी तरह संकीर्णतावादी और कठमुल्लावादी था।

1929 में मेरठ की गिरफ्तारी के बाद बाहर बचे कम्युनिस्टों ने हास्यास्पद रुप से संकीर्ण रुख अपनाया और जवाहरलाल नेहरू को लीग अगेंस्ट इंपिरियलिज्म (साम्राज्यवाद विरोधी लीग) से निकाल बाहर कर दिया! नेहरू को उन्होंने भारत की आजादी का गद्दार करार दे दिया!!

1935 में पी सी जोशी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महामंत्री बनाए गए उनके नेतृत्व में पार्टी में स्थिति सुधरने लगी। जोशी ने राष्ट्रीय मोर्चा का नारा प्रस्तुत किया।

आरपीडी, नेहरू और बोस

आरपीडी की मुलाकात नेहरू से 1936 की फरवरी में स्विट्जरलैंड में हुई। वे दोनों लगभग 16 घंटे तक साम्राज्यवाद विरोधी संयुक्त मोर्चा के बारे में बात करते रहे। वे जीवन पर्यत परस्पर मित्र बने रहे। अक्सर ही नेहरू कम्युनिस्टों के बारे में अपनी समस्याओं को लेकर आरपीडी से विचार विमर्श किया करते। कई बार तो आरपीडी को दोनों के बीच बीच–बचाव भी करना पड़ता।

1936 में संपन्न कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू द्वारा दिए गए अध्यक्षीय भाषण पर आरपीडी का गहरा प्रभाव दीख पड़ता है। नेहरू ने कई मौकों पर कम्युनिस्टों की बड़ी मदद की। नेहरू इस बात से पूरी तरह सहमत थे कि समाजवाद अस्पष्ट मानवतावादी दृष्टि से नहीं बल्कि वैज्ञानिक औरआर्थिक दृष्टि से सही था।

नेहरू ने लखनऊ में दत्त ब्रेडले थीसिस के दो प्रमुख बिंदुओं की वकालत की। इनका उल्लेख हम पहले कर आए हैं। उनका भाषण पूर्ण रूप में आरपीडी के **लेबर मंथली** में प्रकाशित किया गया। जोशी के नेतृत्व में भाकपा की केंद्रीय कमेटी ने 24 जुलाई 1936 को घोषित किया कि नेहरू द्वारा दिया गया भाषण सबसे स्पष्ट रूप में साम्राज्यवाद विरोधी भाषण था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की। सब्जेक्ट कमिटी ने संबद्धता के बारे में के प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए। इसके

शेष पेज 15 पर...

एक कहावत ने अमरीकी नंगापन को उधेड़ कर रख दिया

सुमन्त

कभी कभी रोजमर्रे के जीवन के हमारे कार्य व्यापार में धड़ल्ले से इस्तेमाल होने वाली कोई सामान्य सी कहावत अपने इतने प्रबल अर्थ के रूप में प्रकट हो जाती है कि हम अवाक रह जाते हैं। अब इसी कहावत को लीजिएः 'उल्टे चोर कोतवाल को डांटे!' इसका इस्तेमाल हम रोजमर्रे के जीवन में इतने धड़ल्ले और सहज ढंग से करते होते हैं कि एक स्तर पर जा कर यह बेमानी सा लगने लगती है। लेकिन, यही कहावत आज सामान्य जीवन की नहीं बल्कि आज की राजनीतिक परिदृश्य और वह भी अंतरराष्ट्रीय राजनय में घटित होने वाली एक निहायत निर्लज्जता को उद्घाटित करने का कारण बन गयी है, तो यह हमारे आपके यानी सबके ताज्जुब होने का सबब तो है ही! आइये, असली मुद्दे पर आते हैं।

अभी पिछले शुक्रवार को अमेरिकी प्रशासन ने भारत यात्रा पर जाने के इच्छुक अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें अमेरिका ने अपने नागरिकों से 'अपराध और आतंकवाद' के कारण भारत की यात्रा करते वक्त अधिक सावधानी बरतने को कहा है। यही नहीं, अमरिकी विदेश विभाग ने अपने नागरिकों को जम्मू–कश्मीर की यात्रा नहीं करने की सलाह भी दी है। अमरिकी विदेश विभाग ने यह एडवाइजरी शुक्रवार को जारी की है। इतना ही नहीं अमेरिका ने पाकिस्तान की यात्रा को लेकर भी अपने नागरिकों को सचेत किया है (पीटीआई)।

'अपराध' और 'आतंकवाद'! भारत के आज के हालात के संदर्भ में देखें तो किसी भी निर्दोष नागरिक को यह लग सकता है कि इसमें गलत ही क्या है! भारत के कुछ विशेष अंदरुनी हिस्से में आज जिस प्रकार अपराध और आतंकवादी वारदातों का सिलसिला बढ़ा है, उसे देखते हुए क्यों न लगे कि अमरीका ने अपने नागरिकों को उचित ही तो सलाह दी है! हालांकि, सत्य ये भी है कि भारत में इन वारदातों को विश्व की बेलगाम आवारा पूंजी (जिसमें अमरीका की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है) की दैत्य–भूख के आगे मोदी सरकार के दासानुदास होने के नतीजे के रूप में ही देखी जानी चाहिए। फिर भी, अपने नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से अमरीकी प्रशासन की इस एडवाइजरी पर ऊंगली उठाने की गुस्ताखी को शायद ही कोई पसंद करे!

मगर, जब आप स्वयं अमरीका के अंदर घट रही अपराध और आतंक की कुछ दिल दहला देने वाली बिल्कुल ताजी घटनाओं पर गहरी नजर डालें तो आपको 'उल्टे चोर कोतवाल को डांटे' के लपेटे में अमरीका का नंगापन आपको आईने की तरह साफ साफ नजर आने लगेगा! वह किस तरह, इसे देखने के लिए आइये उन कुछ नृशंस घटनाओं जिनके शिकार अमरीका में रह रहे भारत के मूल लोग हुए हैं, की पड़ताल कर लें।

इस एडवाइजरी के जारी होने के ठीक सप्ताह भर पहले अमरीका के कैलिफोर्निया तथा इंडियाना प्रांत में दो दिल दहला देने वाली आतंक की घटना घटित होती है। कैलिफोर्निया में विगत सोमवार को मूल रूप से पंजाब के होशियारपुर के हरसी पिंड के रहने वाले एक परिवार का अपहरण कर लिया जाता है। पुलिस के लाख प्रयास के बाद भी अपहृत परिवार का पता नहीं लगाया जा सका और ठीक दो दिन बाद आठ माह की बच्ची आरुही धेरी, उसकी मां जसलीन कौर (27), पिता जसदीप सिंह (36), और जसदीप सिंह के भाई अमनदीप सिंह (39) की मृत देह इंडियाना रोड एंड हचिंसन रोड के पास एक बगीचे से बरामद की जाती है। इन शवों को सबसे पहले निकट के खेत में काम करने वाले एक मजदूर ने देखा और उसने पुलिस को खबर की। कैलिफोर्निया के मर्सेड काउंटी के शेरिफ वर्न वार्नके ने शव बरामदी के तुरंत बाद एक संवाददाता सम्मेलन में इस कांड से अत्यंत मर्माहत होते हुए कहा, 'मैं अपना रोष शब्दों में बयां नहीं कर सकता।' और संदिग्ध अपहरणकर्ता 11 साल की जेल काट चुका जीसस मैन्युअल सालगाडो को एक तरह से श्राप देते हुए उन्होंने कहा, 'इस इंसान को नर्क में जगह मिलेगी।'

अमरीका में भारतीयों की मौत के तांडव की दूसरी घटना भी ठीक उसी दिन अमेरिका के इंडियाना प्रांत में एक विश्वविद्यालय परिसर में घटती है। मामला छात्रावास में रह रहे भारतीय मूल के 20 वर्षीय छात्र वरुण मनीष छेड़ा की हत्या से संबंधित है। वरुण परड्यू यूनिवर्सिटी में डेटा साइंस विषय की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस के मुताबिक वरुण यूनिवर्सिटी परिसर के पश्चिमी छोर पर स्थित मैक्चियान हाल में मृत पाया गया था। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वरुण की मौत 'कई घातक चोटों' के कारण हुई व उसकी हत्या किये जाने की आशंका बतायी गयी है। पुलिस प्रमुख वीटे ने कहा कि हमला 'अकारण' किया गया है। वरुण के एक भारतीय दोस्त अरुणाभ सिन्हा ने बताया कि वरुण रात में अपने दोस्तों के साथ आनलाइन बातचीत कर रहा था तभी उन्हें काल पर अचानक चीखने की आवाज सुनायी दी। मगर, वे समझ नहीं पाये कि वहां हुआ क्या है। और दूसरे दिन सुबह जब वे उठे तो उन्हें वरुण की मौत की खबर का पता चला।

भारतवंशी लोगों को मौत का शिकार बनाने की इन भयावह वारदातों को छोड़ भी दें तो बंदूक संबंधी अपनी खुली लाइसेंस नीति के चलते अमरीका इन दिनों अपने ही नागरिकों खासतौर पर स्कूलों के छात्रों को आये दिन मौत के मुंह में ढकेलने की आतंकी घटनाओं से किस तरह त्रस्त है, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं रह गयी है! यानी हम कह सकते हैं कि विश्वभर में अपनी दादागिरी के लिए बदनाम अमरीकी प्रशासन आज खुद के देश के भीतर अपराधियों/आतंकवादियों द्वारा अंजाम दिये जा रहे नृशंस कांड से न तो स्वयं अपने नागरिकों और न ही वहां रह रहे भारतवंशी अथवा अन्य देशों के नागरिकों को शिकार न होने देने में बेहद नाकारा साबित होता नजर आ रहा है!

माना कि भारत में 'अपराध और आतंक' की वारदातों में इधर इजाफा हुई हैं, मगर इस मामले में दूध का धुला तो अमरीका भी कतई नजर नहीं आ रहा है! देखें तो अभी जिस तरह से अमरीका के भीतर भारतीय मूल के लोगों को 'अपराध और आतंक' के जरिए मौत के मुंह में झोंकने की ये जो दो घटनाएं घटी हैं, उससे तो अमरीका ही कटघरे में खड़े होने का सबसे बड़ा अपराधी होता साफ साफ दिख रहा है!

ऐसे में भारत जाने वाले अपने नागरिकों के लिए इस अमरीकी चेतावनी (एडवाइजरी) का क्या अर्थ लगाया जा सकता है! भारत को विश्व बिरादरी में सरासर बदनाम करने की अमरीकी साजिश या मोदी सरकार की झुकी कमर को अपनी ओर और झुकाने की एक नयी अमरीकी तरतीब? यदि हम इस राजनीतिक पेंच वाले पचड़े में न भी फंसे तो डंके की चोट पर यह तो कहा ही जा सकता है कि सामान्य सी दिखने वाली इस कहावत 'उल्टे चोर कोतवाल को डांटे' ने अपनी अर्थवेत्ता से आज अमरीकी प्रशासन के नंगापन को उधेड़ कर रख दिया है!

मच्छरजनित रोगों से निपटने को ठोस कदम उठाए राज्य सरकार: भाकपा

लखनऊ, 31 अक्तूबर 2022: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि मच्छरों से निपटने और साज सफाई में कोताही से माह अक्तूबर के उत्तरार्ध में प्रदेश में मच्छरजनित रोगों– मलेरिया डेंगू चिकनगुनियाँ और स्वाइनफ्लू ने छलांग लगाई है। राजधानी लखनऊ सहित गजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर अथवा कानपुर इनकी अधिक चपेट में हैं।

यहाँ जारी एक प्रेस बयान में भाकपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉ. गिरीश एवं राज्य सचिव अरविन्दराज स्वरूप ने इसके लिए राजकीय व्यवस्थाओं को जिम्मेदार ठहराया है। आरोप लगाया है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवायें तो लचर और लाचार हैं ही रोगों को रोकने के प्राथमिक उपाय किये ही नहीं गये। अधिकतर नगरीय क्षेत्रों में गंदगी के ढेर पसरे पड़े हैं, नालियों खाली प्लाटों और सड़कों में बने गड्ढों में जल जमाव है और फागिंग का काम कागजों तक सिमटा है। जब प्रदेश की राजधानी में ही मच्छरों का असहनीय प्रकोप है तो अन्य जगहों का सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

भाकपा नेताओं ने कहा कि रोगों की व्यापकता को सरकारी आंकड़ों से नहीं मापा जा सकता क्योंकि तमाम लोग धनाभाव में निजी तौर पर घरों में अथवा झोला ब्रांड चिकित्सकों से इलाज करा रहे हैं और सरकारी चिकित्सा तंत्र के रिकार्ड से बाहर हैं। भाकपा नेताओं का आरोप है कि सरकार की दिलचस्पी जनहित में न हो कर वोटों का गणित बिठाने में अधिक है। जितना ध्यान अयोध्या में 18 लाख दीपक जलाने पर लगाया गया और खर्च किया गया, उसका आधा भी यदि बीमारी फैलने से रोकने पर लगाया गया होता तो यह स्थिति न होती।

भाकपा ने मांग की कि "फील्ड स्वास्थ्य टीमों" का गठन कर घर घर इलाज मुहैया कराये जाये, गांवों– शहरों में फागिंग कराई जाये, सड़कों गलियों गड्ढों और खाली जगहों पर जल जमाव और गंदगी के पड़ाव हटाये जाएँ तथा सड़कों पर कूड़ा फैंकने वालों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किये जायें। हर स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी इसकी जांच करें, और जिम्मेदारी सुनिश्चित कर कार्यवाही करें।

इला भट्ट नहीं रहीं–एटक ने भेजी संवेदनाएं

नई दिल्लीः अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक गांधीवादी, श्रम अधिकार कार्यकर्ता और स्व–नियोजित महिला संघ (सेवा) की संस्थापक इला भट्ट के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। वह 86 वर्ष की हैं और हाल तक सेवा गतिविधियों से सक्रिय रूप से जुड़ी रहीं। उनकी मृत्यु भारत श्रम अधिकार आंदोलन के लिए एक क्षति है। एटक ने इला भट्ट के सम्मान में अपना झंडा झुकाया और उनके परिवार और सेवा के शोक संतप्त सदस्यों की पीड़ा को साझा किया।

श्रमिकों और महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध, इला भट्ट ने अपने योगदान के लिए प्रशंसा हासिल की है। वह दुनिया के नेताओं के समूह 'द एल्डर्स' की सदस्य थीं, जिसे नेल्सन मंडेला और डेसमंड टूटू ने फिलिस्तीन मुद्दे सहित कुछ अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर जागृति देने के लिए बनाया था। उनकी कड़ी मेहनत ने पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की। इला भट्ट के प्रतिबद्ध कार्यो से लाखों महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई।

इस मोड़ पर जब श्रम अधिकारों और महिलाओं को अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और उनसे अधिकार छीने जा रहे हैं, इतिहास के इस महत्वपूर्ण समय में जब इस देश में ट्रेड यूनियन आंदोलन कड़ी मेहनत से जीते गए अधिकारों को बनाए रखने के लिए और उन्हें बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है ऐसे समय में इला भट्ट का जाना वास्तव में एक बहुत बड़ी क्षति है।

उनकी विरासत को पूरी प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास के साथ सेवा द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है।

विज्ञान और पर्यावरण पर प्रस्ताव

जरूरत है रिसर्च फंड को बढ़ाने की

डॉ. सोमा मार्ला

आज की ज्ञान अर्थव्यवस्था में विज्ञान में रिसर्च की भूमिका अनिवार्य है ताकि पश्चिमी बहु–राष्ट्रीय कंपनियों से हमें स्वतंत्रता मिले और हम अपना विकास आत्म –निर्भर रूप से कर सकें। भारत में मानव–स्वास्थ्य, मौसम परिवर्तन, हाइड्रजन फ्यूलसेल्स, नव ऊर्जा, क्वांटम कम्प्यूटिंग, सीओ 2 –से– ईधन, नाभिकीय, अंतरिक्ष और कृषि, जैसे क्षेत्रों में मूलभूत रिसर्च अत्यावश्यक है उत्पादक शक्तियों में सुधार के लिए और जनता को नए उत्पाद उपलब्ध कराने के विकास के लिए। वैक्सीनों की कमी, जीवन रक्षक दवाइयोंऔर मेडिकल उपकरणों की कमी को कोविड महामारी के दौरान स्पष्ट रूप से देखा गया था।

भारत में बुनियादी विज्ञान शोध पर्याप्त फंड के अभाव से तंगहाल है। भाजपा सरकार अपने केन्द्रीय बजट में सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.66 प्रतिशत आवंटित करती है। देशभर में आईआईटी, विश्वविद्यालयों और विभिन्न नेशनल रिसर्च इंस्टिट्यूट के लिए विज्ञान और तकनीक मंत्रालय द्वारा 2022–23 के लिए 266 उत्पादों के संचालन के लिए वेतन के भुगतान, अन्य खर्चों के भुगतान के लिए मात्र 4.25 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। ब्राजील जैसे कई देश जो की मध्यम आय वर्ग में हैं वे अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2–3 प्रतिशत शोध और विकास (आरएण्डडी) पर खर्च कर रहे हैं।

सरकार को केन्द्रीय बजट में सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत वैज्ञानिक रिसर्च पर खर्च करना चाहिए।

सरकार को नई खोज और आविष्कार करने वाले सराहनीय काम के लिए वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कारों को फिर से चालू करना चाहिए।

पर्यावरणीय कानूनों का विलयन

पिछले दो सालों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने नए संशोधन पेश किए और "जैवविविधता कानून" और "वन अधिकार कानून 2006" और "तटीय क्षेत्र संरक्षण कानून" का विलय किया है।

ये सब किया गया है फार्मासुटिकल इंडस्ट्री (औषधीय उद्योग) को आरक्षित वन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए और दुर्लभ औषधीय और अन्य पौधों की लूट के लिए जिसमें उनके ऊपर कोई नियम रुकावट ना हो। यह केवल भारतीय और बहुराष्ट्रीय औषधीय उद्योगों को स्थानीय आदिवासियों को बिना किसी मुआवजे के वनों की लूट की छूट देता है।

संशोधित नए कानून बड़े भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खनन का अधिकार देता है।

तटीय क्षेत्र संरक्षण कानून में नए संशोधन समुद्र तट पर होटलों और अन्य निजी व्यवसायों के लिए आरक्षित 1 किलोमीटर की दूरी की जगह 500 मीटर पर निर्माण की अनुमति देता है। समुन्द्र तट संरक्षण सीमा में 1 किलोमीटर से कम कर 500 मीटर की दूरी मैनग्रोव, मछुआरों और उनकी आजीविका को प्रभावित करेगा और निजी रेत खनन में सहायक होगा।

दलितों पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ जवाबी लड़ाई का संकल्प

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं काँग्रेस देश में दलितों पर बढ़ते अत्याचारों पर अपने चिंताजनक सरोकार व्यक्त करती है। 2014 से जब से आरएसएस–भाजपा शासन केंद्र में है तब से पुलिस के पास आधिकारिक रूप से अत्याचारों के लाखों मामले दर्ज हैं। यहाँ तक कि एक बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज किए बिना रह जाती हैं। पिछले दस सालों के दौरान 4000 से ज्यादा दलित मारे जा चुके हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्डस ब्युरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अत्याचारों पर दर्ज मामलों 2019 में 45, 961 से बढ़कर 2021 में 50, 900 हो गए हैं और यह दिखाता है कि देश में दलितों पर अत्याचार के मामले 11 प्रतिशत बढ़े हैं। देश भर में दलितों पर अत्याचार अबाधित रूप से चालू है, और भाजपा द्वारा शासित राज्यों में दलितों पर अपराध के आँकड़े अधिक मामले दिखाते हैं।

समाज के हाशियाई तबके के खिलाफ अत्याचार के मामलों में बढ़ोतरी, सामूहिक दुष्कर्म और भीड़ हत्या अखंड रूप से भाजपा के दलितों और दमित तबकों के हाशियाई कारण के साथ जुड़ी है। 1989 के अत्याचार अधिनियम के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निवारण को पहले भी किसी भी सरकार द्वारा पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। राज्यों में भाजपा सरकारों ने इन हमलावरों की अगुआई करने वाले अपराधियों को सरंक्षण देने से और आगे चले गए हैं।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं पार्टी काँग्रेस सामाजिक न्याय, वाम और जनतान्त्रिक ताकतों, जन संगठनों और ट्रेड यूनियनों सभी से आह्वान करती है कि दलितों और अन्य कमजोर तबकों पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की काँग्रेस संकल्प लेती है कि इन अत्याचारों के खिलाफ अपना संघर्ष सघन कारेंगें और सरकार से मांग करती है कि दलितों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने के उपाय करे और अत्याचार अधिनियम के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निवारण को मजबूत करे और लागू करने के साथ–साथ सुनिश्चित करे कि दलितों पर हमला करने वाले अपराधियों पर मामले दर्ज किए जाएंगे और उन पर सख्त कार्यवाई की जाएगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दिल्ली में 5 नवंबर को दलितों और आदिवासियों पर हमलों के खिलाफ होने वाले राष्ट्रीय कन्वेन्शन का समर्थन करती है।

बांग्लादेश कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से अभिनंदन संदेश

कामरेड अध्यक्ष, सभामंडल के सदस्यों, विभिन्न देशों से आए बिरादराना पार्टियों के सम्मानित प्रतिनिधियों, भाकपा की 24वीं काँग्रेस के सम्मानित प्रतिनिधियों, भाइयों और बहनों, नामी मेहमानों, पत्रकारों, मैं, बांग्लादेश कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष, मुहम्मद शाह आलम और यहाँ इस सत्र में उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय विभाग के प्रमुख और हमारी पार्टी के केन्द्रीय समिति के सदस्य एडवोकेट हसन तारिक चौधरी आप सभी का अभिनंदन करते हैं। हम बांग्लादेश कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। बांग्लादेश कम्युनिस्ट पार्टी आपकी काँग्रेस की पूर्ण सफलता की कामना करती है।

प्रिय साथियों,

ऐतिहासिक रूप से हमारी पार्टी (सीपीबी) 1947 में भारत के विभाजन से पहले अविभाजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सांप्रदायिक विचार और राजनीति के आधार पर भारत के विभाजन के कारण, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन लगभग दो शताब्दी तक सफल नहीं हुआ और असफल रहा। नतीजतन, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के भारत छोड़ने के 75 साल बाद भी उपमहाद्वीप के लोगों को सांप्रदायिक राजनीति के जहर से मुक्त नहीं किया जा सकता था। अगर भारत का विभाजन नहीं होता तो क्या कश्मीर संकट पैदा होता? एनआरसी की सांप्रदायिक राजनीति का सवाल नहीं उठता तो नेशनल रजिस्टर आ पाता? यह बहुत स्पष्ट है कि सांप्रदायिक राजनीति ने बांग्लादेश और पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना को बर्बाद कर दिया है, अब भारत में सांप्रदायिक हिंदुत्व की राजनीति भारत के बुर्जुआ लोकतंत्र को कई गुना कम कर रही है।

सांप्रदायवाद को एक नए तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, साम्राज्यवादी वैश्विक पूंजी द्वारा एक नई हद तक ताकि यह अपनी नवउदार पूंजीवादी नीतियों को लागू कर सके।

हम नवउदार अर्थव्यवस्था और पूंजीवाद के चरित्र को जानते हैं। इस पूंजीवाद का चरित्र है:

1. जनतंत्र–विरोधी
2. जन–विरोधी
3. धर्मनिरपेक्ष–विरोधी
4. पर्यावरण शत्रु
5. अर्थव्यवस्था में फासीवादी तत्वों का आना

यह पूंजीवाद चरम राष्ट्रवाद, नस्लवाद, संप्रदायवाद आदि का उपयोग कर रहा है। दुनिया भर में एक उपकरण के रूप में इस अर्थव्यवस्था को लागू करने के लिए। इसके वैश्विक साम्राज्यवादी हितों के लिए, वे दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में युद्ध गठबंधन और सैन्य समझौते बना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने क्वाड सिक्योरिटी नामक एक सैन्य गठबंधन बनाया है। विश्व साम्राज्यवाद की इस गतिविधि ने उपमहाद्वीप और प्रशांत क्षेत्र में भू–राजनीतिक गतिविधि को बढ़ाया है। इस गतिविधि ने उपमहाद्वीप की राजनीति को भी प्रभावित किया है।

प्यारे साथियों,

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को अस्थिर कर दिया है। परमाणु युद्ध के खतरे की भी दुनिया सुन रही है। ताइवान पर अमेरिकी गतिविधियों ने दक्षिण चीन सागर में सैन्य चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में भारत–अमरीकी सैन्य भागीदारी में वृद्धि सभी लोकतांत्रिक ताकतों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। रूस और यूक्रेन के बीच इस युद्ध के परिणाम से दुनिया का सामाजिक–आर्थिक राजनीतिक संतुलन बदल जाएगा।

1947 के बाद से, हमने पाकिस्तानी शासक वर्ग के दमनकारी और भेदभावपूर्ण शासन के खिलाफ स्वायत्तता और लोकतंत्र के लिए लंबा संघर्ष किया है, लेकिन अंत में हमें एक सशस्त्र मुक्ति युद्ध करना पड़ा जिसमें वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग ने प्रमुख भूमिका निभाई। हमारी पार्टी, सीपीबी ने भी मुक्ति संग्राम में केंद्रीय भूमिका निभाई और मुक्ति संग्राम के दौरान हमारे पास अलग गुरिल्ला टुकड़ी थी। हमारे मुक्ति संग्राम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने महत्वपूर्ण समर्थन दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने हमारे मुक्ति संग्राम को भरपूर समर्थन दिया। उस समय समाजवादी सोवियत संघ की भूमिका ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण थी। 16 दिसंबर 1971 को, नौ महीने के सशस्त्र मुक्ति युद्ध के बाद, पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को हराया गया था। हमने जीत हासिल की, देश आजाद हुआ। देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति और विचारधारा की प्रतिक्रियावादी प्रवृत्ति के खिलाफ प्रगति की यात्रा शुरू हुई। लेकिन 15 अगस्त 1975 में राष्ट्रीय नेता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की नृशंस हत्या के बाद, तथाकथित पाकिस्तानी प्रतिक्रियावादी प्रवृत्ति को बहाल किया गया था जो अभी भी चालू है।

वर्तमान में हमारे देश में सरकार और विपक्षी दल नव–उदार अर्थव्यवस्था के अनुयायी हैं, जिसके परिणामस्वरूप साम्राज्यवादी परजीवियों और उच्च वर्ग ने अपने वर्ग के हितों के लिए सांप्रदायिकता का इस्तेमाल किया और देश से लोकतंत्र को निर्वासित कर दिया।

इसलिए हमारी पार्टी ने एक वामपंथी लोकतांत्रिक वैकल्पिक शक्तियों को एकजुट करने की पहल की है, जिसमें हमारे देश के लूटेरे द्विदलीय दायरे के बाहर, राष्ट्रीय कार्य और वर्ग कार्य शामिल हैं और हम अपनी राष्ट्रीय राजनीति में वामपंथी लोकतांत्रिक विकल्प के हित को बढ़ाने के लिए मजबूत प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमने छह दलों वाला वाम लोकतांत्रिक गठबंधन बनाया है।

प्यारे साथियों,

विश्व और उपमहाद्वीप की वर्तमान स्थिति में, हमारी पार्टी दृढ़ता से मानती है कि उपमहाद्वीप की कम्युनिस्ट वामपंथी प्रगतिशील ताकतों के बीच पारस्परिक संवाद, राय और संचार की पहल करना आवश्यक है। नव फासीवादी और साम्राज्यवादी हमलों का मुकाबला करने के लिए बहुत मजबूत क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाना यह सब हमारे क्रांतिकारी काम हैं।

दुनिया के मजदूरों एक हो! लाल सलाम!

बांग्लादेश कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बीच मित्रता जिन्दाबाद!

बांग्लादेश और भारत के बीच मित्रता जिन्दाबाद!

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं कांग्रेस में पारित प्रस्ताव

सार्वजनिक क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्र को विघटन से बचाने और सरकारी नौकरियों एवं सार्वजनिक क्षेत्र में खाली पड़े 14 लाख पदों को तत्काल भरने के संबंध में

विजयवाड़ा में 14 से 18 अक्टूबर 2022 तक हो रही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं कांग्रेस ने सरकार द्वारा सार्वजनिक एवं सरकारी क्षेत्र को पूरी तरह से विघटित करने और स्वतंत्रता के बाद 70 से अधिक वर्षों में बनाई गई राष्ट्रीय परिसंपत्तियों को निजी कारपोरेटों और याराना पूंजीपतियों के हवाले किए जाने के सरकार के नीतिगत फैसले का गंभीर नोट लिया है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाइन के नाम पर सार्वजनिक क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्र को सरकार के कृपाप्राप्त निजी कारपारेटों के हवाले किया जा रहा है। राष्ट्र के सार्वजनिक एवं सरकारी क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था के विकास, औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक एवं आर्थिक तौर पर दबे–कुचले समुदायों को रोजगार में आरक्षण प्रदान कर सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमका अदा की है। वर्तमान सरकार के तहत आज यह क्षेत्र गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं।

सरकारी विभागों में भी फिक्स्ड टर्म रोजगार और काम का ठेकाकरण दिन–प्रतिदिन बढ़ रहा है। इससे प्रशासन एवं नागरिक सेवा में कमजोरी आती है जिससे अंततः उस आम आदमी पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा जो सरकारी व्यवस्था से मिलने वाले लाभों एवं अन्य दिन–प्रतिदिन की आवश्यकताओं से वंचित हो जाएगा।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं कांग्रेस ने इस बात का भी अत्यंत गंभीरता से नोट लिया है कि केंद्र सरकार के संगठनों जैसे कि रेलवे, रक्षा, पोस्टल सेवा आदि में 10 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं। सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग में 4 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं। भारत जैसे देश में जहां दो करोड़ से अधिक युवा बेरोजगार हैं परंतु भाजपा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध इन खाली पड़े पदों को नहीं भर रही है और मूकदर्शक बनी हुई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सामाजिक न्याय एवं बेरोजगारी के प्रति सरकार के असंवेदनशील रवैये की भर्त्सना करती है और मांग करती है कि सार्वजनिक क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्र को मजबूत और विस्तारित किया जाना चाहिए और निजीकरण को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्र में खाली पड़े 14 लाख पदों को तुरंत भरा जाना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देश की जनता का आह्वान करती है कि सार्वजनिक क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्र को खत्म किए जाने से बचाने के लिए आवाज बुलंद करे।

41 ऑडनेंस (आयुध) फैक्टरियों को सात कारपोरेशनों में बदलने के सरकार के फैसले को वापस लेने और सरकारी रक्षा उद्योग पर हमला बंद करने के संबंध में

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 220 वर्ष पुरानी आयुध फैक्टरियों को सात कारपोरेशनों में बदलने के भारत सरकार से एकतरफा फैसले का शुरू से ही विरोध किया है। सरकार ने दावा किया कि यह सात कारपोरेशनें शत–प्रतिशत सरकार के स्वामित्व में हैं और कारपोरेशन बनाने के बाद सरकार इन सात कारपोरेशनों की मदद करती रहेगी। कारपोरेटीकरण के एक साल के बाद देखा जा रहा है कि सरकार रक्षा उद्योग को बीमार करने और कुछ समय बाद आयुध फैक्टरियों का विनिवेश करने और निजीकरण करने के अव्यक्त उद्देश्य के साथ उन्हें कोई समर्थन नहीं दे रही है। हाल में सेना मुख्यालय ने सेना युद्ध वर्दी की खरीद के लिए एक टेंडर निकाला है जिसे टीसीएल के अंतर्गत चार आयुध फैक्टरियों की उपेक्षा कर निजी स्रोतों से डिजिटली प्रिंट कराया गया। टेंडर में जो शर्तें दी गई हैं उनमें भी कुछ चयनित निजी फर्मों पर कृपा–दृष्टि के लिए मुख्य सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देशों का साफतौर पर उल्लंघन किया गया है। अन्य आयुध फैक्टरियों में बनाए जाने वाले अन्य रक्षा उपकरणों के मामले में भी इसी तरह के टेंडर निकाले जाने की संभावना है। यह हमारे देश की रक्षा तैयारियों और उन 76,000 रक्षा असैन्य कर्मचारियों के हित में नहीं है जिन्हें इन सात कारपोरेशनों और 41 आयुध फैक्टरियों में डेपुटेशन पर समझा जाता है। आयुध फैक्टरियां ही अकेली नहीं है जिनपर हमला हो रहा है, डीआरडीओ (डिफेंस रिसर्च एंड डवलपमेंट ऑर्गेनाईजेशन) समेत समूचा रक्षा उद्योग निजीकरण के कगार पर है। पहले ही सरकार रक्षा अनुसंधान एवं विकास में निजी उद्योगों की हिस्सेदारी के लिए डीआरडीओ के बजट के 25 प्रतिशत का आवंटन कर चुकी है।

विजयवाड़ा में 14 से 18 अक्टूबर 2022 तक हो रही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं कांग्रेस भारत सरकार से मांग करती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं देश की रक्षा तैयारियों के हित में आयुध फैक्टरियों के कारपोरेटीकरण को वापस ले और इसे फिर से सरकार के सीधे नियंत्रण में ले और पूरी तरह आत्मनिर्भरता एवं रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को हासिल करने के लिए आयुध फैक्टरियों को मजबूत और विस्तारित करे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यह मांग भी करती है कि भारत सरकार को चाहिए कि रक्षा से संबंधित कार्यकलापों को निजी कारपोरेटों के हवाले करने से बाज आए और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सरकारी रक्षा उद्योग को मजबूत बनाए।

नई पेंशन स्कीम, जिसमें पेंशन की कोई गारंटी नहीं, को रद्द किया जाए और केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारियों एवं बैंकों, बीमा समेत अन्य क्षेत्रों में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के संबंध में

विजयवाड़ा में 14 से 18 अक्टूबर 2022 तक हो रही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं कांग्रेस ने गंभीर चिंता के साथ नोट किया है कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित एवं गारंटीशुदा पुरानी पेंशन स्कीम के स्थान पर सरकार ने अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम को लागू किया। सरकार का यह कदम पूरी तरह विफल हुआ है और यह सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महाविपदा की बात है। एनपीएस को बैंकों, बीमा आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया गया है। एनपीएस विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के आदेशों का परिणाम है और उत्तरोत्तर सरकारों द्वारा अनुसरित नव उदारवादी नीतियों के आधार पर इसे लागू किया गया। कर्मचारियों और सरकार के अंशदान से जमा खरबों रुपयों को पीएफआरडीए के जरिये बाजार में लगाया जा रहा है और ये निवेश बिना किसी गारंटी और सुरक्षा के किए जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बाजार की ताकतों पर निर्भर नहीं रह सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि ''पेंशन कोई ईनाम नहीं है, पेंशन कोई तोहफा नहीं है, पेंशन कोई एक्स–ग्रेशिया (अनुग्रह राशि) नहीं है, पेंशन सरकारी कर्मचारियों का एक मूलभूत अधिकार है।'' इस एनपीएस को लागू किए जाने के बाद देखा गया है कि जो कर्मचारी अब सेवानिवृत्त होना शुरू हुए हैं उन्हें एनपीएस से दो से 4 हजार रुपए की मामूली–सी पेंशन मिल रही है। वही कर्मचारी यदि पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत होते तो उन्हें 20 से 30 हजार रुपए की मासिक पेंशन मिलती और महंगाई की पूर्ति के लिए महंगाई भत्ता मिलता। इस स्कीम से सरकारी कर्मचारी दो वर्गों में बंट जाते हैं और यह पूरी तरह भेदभावपूर्ण है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं कांग्रेस संतोष व्यक्त करती है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसी राज्य सरकारों ने एनपीएस को वापस ले लिया है और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं कांग्रेस भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों से मांग करती है कि एनपीएस को तत्काल रद्द करे और पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करे। एनपीएस के खिलाफ उनके संघर्ष को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपना समर्थन देती है और उनके संघर्ष के लिए अपनी एकजुटता व्यक्त करती है।

कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने के मुस्लिम छात्राओं के अधिकार के संबंध में

हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने पर रोक को चुनौती देने वाली अपीलों पर एक विभाजित फैसला लिया। इसमें जस्टिस सुधांशु धुलिया ने विचार व्यक्त किया कि हिजाब पहनना अंततः व्यक्तिगत पसंद का मामला है; यह धार्मिक प्रैक्टिसों की अवधारणा नहीं है और इस कारण किसी को भी इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उनके इस दृष्टिकोण का सुविचारित तौर पर समर्थन करती है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं कांग्रेस भाजपा शासित कर्नाटक राज्य में इस मुद्दे के संप्रदायीकरण की कोशिश की भर्त्सना करती है।

जाति के आधार पर राष्ट्रीय जनगणना के प्रश्न के संबंध में

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं कांग्रेस जाति आधारित जनगणना की मांग का पूर्ण समर्थन करती है। देश में प्रचलित वास्तविक सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जाति आधारित जनगणना को हमेशा समर्थन दिया है।

जनगणना आरएसएस–भाजपा के इस दावे को खारिज कर सकती है कि भारत अपने स्वर्णयुग में था। परंतु वास्तविकता इससे भिन्न है। भारत के लोगों की वास्तविक स्थिति और आवासन, वित्तीय हैसियत, रोजगार, साक्षरता, भाषा आदि के संबंध में उनके अलग से विवरण आरएसएस–भाजपा सरकार के लिए चुनौती बन सकते हैं। वे इन हरेक बातों के संबंध में मिथ्या निरूपणों को रेखांकित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे वास्तविकता से डरे हुए हैं। जनगणना मात्र एक गणना करने का कार्यक्रम मात्र नहीं है बल्कि यह नागरिकों की एकता के संबंध में संदेश भी है। जनगणना देश की वास्तविकता की एक सही तस्वीर भी पेश करेगी।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मांग करती है कि राष्ट्रीय जनगणना को जाति आधार पर किया जाना चाहिए। वर्ष 2021 में यही किया गया था। परंतु उसे जाहिर नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप अनेक विवाद पैदा हुए। भाजपा सरकार जाति जनगणना को जानबूझकर टाल रही है और जाति विवादों को विभिन्न राज्यों में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का यह दृष्टिकोण भी है कि यदि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा लगाई गई 50 प्रतिशत की वर्तमान रोक में संशोधन नहीं किया गया तो पूरी कवायद निष्फल साबित हो सकती है।

भारत सरकार से चार श्रम संहिताओं को निरस्त करने की मांग के संबंध में

भारतीय मजदूर वर्ग द्वारा अपने एक शताब्दी पुराने संघर्षों से हासिल श्रम कानूनों के साथ भाजपा सरकार ने जिस तरह घालमेल किया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उसका गंभीर नोट लेती है। सरकार ने 29 श्रम कानूनों को एकतरफा तरीके से मिलाते हुए उन्हें चार श्रम संहिताओं का रूप दे दिया है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने इन मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं को निरस्त करने की मांग की। सरकार ने न केवल उनकी मांग को खारिज कर दिया बल्कि श्रम पर संसदीय स्थायी समिति की विभिन्न सिफारिशों को अनदेखा किया। सरकार ने संसद में इन पर विचार की इजाजत दिए बगैर चार श्रम संहिताओं को पारित कर दिया।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी संदिग्ध सुधारों के नाम पर बहुत कठिनाइयों के बाद हासिल किए गए मजदूर वर्ग एवं मेहनतकश लोगों के अधिकारों पर हमला करने की सरकार की कोशिश की भर्त्सना करती है। भाजपा सरकार ने श्रम कानूनों के संहिताकरण के काम को निजी कारपोरेटों एवं बहुराष्ट्रीय निगमों को फायदा पहुंचाने और मेहनतकश लोगों को धोखा देने के लिए किया है। ये चार श्रम संहिताएं यदि एक बार लागू हो गई तो मजदूरों को उस तरह के गुलामी जैसी हालात में पहुंचा देंगे जो 19वीं सदी में मौजूद थे और जिन हालात के खिलाफ भारतीय मजदूर वर्ग ने एटक के नेतृत्व में संघर्ष किया और वर्तमान अधिकारों को हासिल किया था।

भारतीय मजदूर वर्ग और केंद्रीय ट्रेड यूनियनें श्रम कानूनों के इस संहिताकरण के हमले के खिलाफ और अधिकारों एवं सम्मान की रक्षा में दृढ़ संकल्प के साथ एकताबद्ध संघर्ष कर रही हैं। इसके लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उनका अभिनन्दन करती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत सरकार से मांग करती है कि इन मजदूर विरोधी संहिताओं को तत्काल निरस्त करे।

उक्कू परिरक्षा पोरटा कमेटी के बैनर के तहत आन्ध्र प्रदेश के विशाखापट्नम में 600 दिनों से जारी आंदोलन पर प्रस्ताव

14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर, 2022 तक विजयवाड़ा में आयोजित भाकपा की 24वीं पार्टी कांग्रेस उक्कू परिरक्षा पोरट्टा समिति के बैनर तहत भाजपा सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्र की शत–प्रतिशत रणनीतिक बिक्री के निर्णय के खिलाफ जारी आंदोलन के लिए सभी ट्रेड यूनियनों के लोगों, नेताओं और सदस्यों को बधाई देती है। भाकपा विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को निजीकरण से बचाने के लिए लोगों और मजदूरों के अथक संघर्ष के संकल्प की सराहना करती है। यह बड़े संतोष की बात है कि संघर्ष समिति ने सरकार/प्रबंधन द्वारा नियुक्त किसी भी समिति को प्लांट में घुसकर मूल्यांकन का जायजा लेने की अनुमति नहीं दी।

भाकपा, भारत सरकार से अपने फैसले को वापस लेने का आग्रह करती है क्योंकि विशाखापत्तनम स्टील प्लांट 1 करोड़ से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान कर रहा है, और 8 हजार विस्थापित लोगों को जिन्होंने विशाखापत्तनम स्टील प्लांट की स्थापना के लिए जमीन दी है, उन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली है। भाकपा विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को निजीकरण से बचाने के उनके संघर्ष में उक्कू परिरक्षा पोरट्टा समिति के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है और सार्वजनिक क्षेत्र के एक प्रमुख उद्योग को बचाने के लिए उनके सभी कार्य कार्यक्रमों को पूर्ण समर्थन देती है।

डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों की सेवा शर्तों पर प्रस्ताव

डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों की मौजूदा सेवा शर्तों के मुताबिक अल्प भुगतान के बारे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं काँग्रेस गंभीरता से ध्यान देती है। ग्रामीण डाक सेवकों को सिवल सर्वेन्टस का दर्जा देने के अनवरत संघर्ष के बावजूद तत्कालीन और परवर्ती सरकारों ने अपने कान बंद कर रखे हैं।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अनुरोध करती है भारत सरकार से कि सभी ग्रामीण डाक सेवक शाखाओं के ग्रामीण डाक सेवकों के 4 से 5 कार्य घंटों को बढ़ाकर 8 घंटे करने के द्वारा सिवल सर्वेन्टस का दर्जा दिया जाए। ग्रामीण डाक सेवकों को गारंटीशुदा परिभाषित पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत भी लाया जा सकता है।

भाजपा–एनडीए कार्पोरेट–उन्मुखी नव–उदार जन–विरोधी नीतियों के खिलाफ हमारे संघर्षों को सघन करने का प्रस्तावः जनता की सुविधा के लिए सरकार से टकराव

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं काँग्रेस विजयवाड़ा के अपने प्रतिनिधि सत्र में उन नव–उदार आर्थिक नीतियों पर खेद प्रकट करती है और भर्त्सना करती है जो कि निर्वस्त्र रूप से जन विरोधी और कार्पोरेट उन्मुखी हैं।

हम नव–उदार नीतियों से पीछे तब 1991 से लड़ रहे हैं जब से वे भारत में शुरू की गई थीं। उदारवाद, निजीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव ने लोगों के बीच अप्रत्याशित असमानता को बढ़ाया और तेज किया है और देश की संपदा का सकेन्द्रण कुछ लोगों के पास है। पीछे 8 साल से ज्यादा, जब से भाजपा नीत मोदी सरकार सत्ता में आई, तब से सुधार एजेंडों में तेजी आई है।

देश का सकल घरेलू उत्पाद 2016 से तब से सिकुड़ रही है जब 2016 से नोटबंदी की गई थी और 2017 से जीएसटी शुरू की गई थी। 2020 में कोविड महामारी के दौरान लॉकडाउन ने आर्थिक मोर्चे पर संकट को बढ़ाया था। सरकार उस समय मात्र दर्शक थी जब करोड़ों परदेशी मजदूर अपने परिवारों और बच्चों के साथ पैदल अपने घरों को लौट रहे थे।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्यूएचओ) का अनुमान है कि भारत में कोरोना के कारण 47 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है, मौत के ये आँकड़े भारत सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों से10 गुना अधिक हैं। तब भी, स्वास्थ्य सेवा के लिए बजटीय आवंटन केवल 2 प्रतिशत है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि लगभग साढ़े छह करोड़ लोगों को स्वास्थ्य के उपर हुए खर्चो के कारण गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिया गया है।

मानव विकास सूचकांक में भारत 133वें और वैश्विक भूख सूचकांक में107वें स्थान पर है भारत की यह स्थिति अपने पड़ोसी देशों जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, और बांग्लादेश से कम है। दूसरी ओर, कंपनियों को रियायतें दी गई हैं। कंपनियों के लिए कारपोरेट कर की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दी गई है और नई विनिर्माण कंपनियों के लिए इसे 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। बड़ी निजी कंपनियों द्वारा बैंक ऋण के बड़े डिफॉल्ट से बेशर्मी से समझौता किया जा रहा है, जिससे कंपनियों को फायदा हो रहा है। बड़ी निजी कंपनियों को सरकार लोगों के पैसे की खुली लूट की सुविधा दे रही है।

ऑक्सफैम इंडिया की "इनएक्विलिटी किलस" (असमानता मारती है) नाम से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में भारत के सबसे अमीर परिवारों की संपत्ति रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। रिपोर्ट में भारत को बहुत असमान देश बताया गया है, क्योंकि भारत में शीर्ष 10 लोगों के पास 57 प्रतिशत संपत्ति है। वहीं, संपत्ति में आबादी के निचले हिस्से का हिस्सा 13 फीसदी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड–19 महामारी के बीच 84 प्रतिशत भारतीय परिवारों की आय में गिरावट आई है। सबसे अमीर 98 भारतीयों के पास वही संपत्ति है जो सबसे नीचे के 5520 लाखों लोगों के पास है। 2021 के दौरान भारतीय अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई है।

कीमतें आसमान छू रही हैं आम जनता के पेट पर मार कर रही हैं। रोजाना भूख से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। श्रम ब्यूरों के अनुसार, 25 प्रतिशत आबादी 19 से 29 वर्ष के बीच है और उन्होंने इस वर्ष के अंत तक 34 प्रतिशत की बेरोजगारी दर को झेलना होगा, जो काफी चिंताजनक है। अग्निपथ योजना जो कि सशस्त्र बलों में भर्ती के उद्देश्य से शुरू की गई है इस से देश के बेरोजगार युवाओं में निराशा बढ़ेगी।

सार्वजनिकक्षेत्र, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, इसे नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने न केवल अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया है, बल्कि दशकों से रोजगार सृजन का स्रोत भी रहा है। हालांकि, भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के अंधाधुंध निजीकरण और राष्ट्रीय परिसंपत्तियों की बिक्री के साथ आगे बढ़ रही है। इस तरह का एक उदाहरण टाटा को एयर इंडिया की बिक्री ना के बराबर दाम पर बेचने का है। बीपीसीएल, सीसीआई, शिपिंग कॉरपोरेशन, बीईएमएल, नीलांचल इस्पात निगम की रणनीतिक बिक्री, एलआईसी का विनिवेश, सामान्य बीमा कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी में कमी और आईडीबीआई बैंक की प्रस्तावित बिक्री के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण की घोषणा और कुछ नहीं केवल उस गति को दिखाती है जिस गति से सुधार के एजंडों को लागू किया जा रहा है। 41 आयुध कारखानों को उनके निजीकरण की योजना के साथ निगमों में बदला गया है। रक्षा विनिर्माण, परमाणु ऊर्जा आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रक्षा क्षेत्र को खोलने से देश की संप्रभुता को खतरे में होगी।

केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) देश के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए एक गंभीर खतरा है। एनएमपी से अगले 4 वर्षो में केंद्र सरकार की प्रमुख परिसंपत्तियों को पट्टे पर देने के माध्यम से लगभग 6 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन होने की उम्मीद है।

जहां तक मजदूर मोर्चो पर हमले हैं, संसद में बिना चर्चा के सरकार द्वारा लाए गए चार श्रम संहिता बड़े पैमाने पर श्रमिक वर्ग को एक निर्णायक झटका देने जा रहे हैं क्योंकि मजबूती से लड़े और जीते हुए श्रम कानूनों को ध्वस्त कर दिया गया है।

वर्तमान में, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में अपने विकास पूर्वानुमान को कम कर दिया है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है। महंगाई लगातार बढ़ रही है और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, आवश्यक वस्तुएं आम लोगों की पहुंच से बाहर जा रही हैं।

इसलिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की काँग्रेस की मांग है कि केंद्र सरकार को अपनी उन वर्तमान विनाशकारी आर्थिक नीतियों को बदलना चाहिए, जिनका उद्देश्य कारपोरेट्स और सर्वोच्च धनाढ्यों के हितों को लाभ देने के लिए है और देश की गरीब जनता और आम लोगों के खिलाफ है। और सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करना चाहिए, विनिर्माण इकाइयों में निवेश करना चाहिए, रोजगार पैदा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों में पूंजी का निवेश करना चाहिए, बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेचने के प्रस्तावों को छोड़ देना चाहिए।

संक्षेप में, भाजपा सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियां लोगों के हितों के लिए हानिकारक हैं और स्पष्ट रूप से कंपनियों के पक्ष में हैं। आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की काँग्रेस जनता को, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे राष्ट्र को बचाने के लिए विनाशकारी आर्थिक नीतियों के खिलाफ संघर्ष जारी रखने और तेज करने का संकल्प करती है।

संगठित होंगे और संघर्ष करेंगे, कोई और विकल्प नहीं है।

विज्ञान और पर्यावरण पर प्रस्ताव जरूरत है रिसर्च फंड को बढ़ाने की

आज की ज्ञान अर्थव्यवस्था में विज्ञान में रिसर्च की भूमिका अनिवार्य है ताकि पश्चिमी बहु–राष्ट्रीय कंपनियों से हमें स्वतंत्रता मिले और हम अपना विकास आत्म –निर्भर रूप से कर सकें। भारत में मानव–स्वास्थ्य, मौसम परिवर्तन, हाइड्रजन फ्यूलसेल्स, नव ऊर्जा, क्वांटम कम्प्यूटिंग, सीओ 2 –से– ईंधन, नाभिकीय, अंतरिक्ष और कृषि, जैसे क्षेत्रों में मूलभूत रिसर्च अत्यावश्यक है उत्पादक शक्तियों में सुधार के लिए और जनता को नए उत्पाद उपलब्ध कराने के विकास के लिए। वैक्सीनों की कमी, जीवन रक्षक दवाइयोंऔर मेडिकल उपकरणों की कमी को कोविड महामारी के दौरान स्पष्ट रूप से देखा गया था।

भारत में बुनियादी विज्ञान शोध पर्याप्त फंड के अभाव से तंगहाल है। भाजपा सरकार अपने केन्द्रीय बजट में सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.66 प्रतिशत आवंटित करती है। देशभर में आईआईटी, विश्वविद्यालयों और विभिन्न नेशनल रिसर्च इंस्टिटयूट के लिए विज्ञान और तकनीक मंत्रालय द्वारा 2022–23 के लिए 266 उत्पादों के संचालन के लिए वेतन के भुगतान, अन्य खर्चो के भुगतान के लिए मात्र 4.25 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। ब्राजील जैसे कई देश जो की मध्यम आय वर्ग में हैं वे अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2–3 प्रतिशत शोध और विकास (आरएण्डडी) पर खर्च कर रहे हैं।

सरकार को केन्द्रीय बजट में सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत वैज्ञानिक रिसर्च पर खर्च करना चाहिए।

सरकार को नई खोज और आविष्कार करने वाले सराहनीय काम के लिए वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कारों को फिर से चालू करना चाहिए।

पर्यावरणीय कानूनों का विलयन

पिछले दो सालों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने नए संशोधन पेश किए और "जैवविविधता कानून" और "वन अधिकार कानून 2006" और "तटीय क्षेत्र संरक्षण कानून" का विलय किया है।

ये सब किया गया है फार्मासुटिकल इंडस्ट्री (औषधीय उद्योग) को आरक्षित वन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए और दुर्लभ औषधीय और अन्य पौधों की लूट के लिए जिसमें उनके ऊपर कोई नियम रुकावट ना हो। यह केवल भारतीय और बहुराष्ट्रीय औषधीय उद्योगों को स्थानीय आदिवासियों को बिना किसी मुआवजे के वनों की लूट की छूट देता है।

संशोधित नए कानून बड़े भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खनन का अधिकार देता है।

तटीय क्षेत्र संरक्षण कानून में नए संशोधन समुद्र तट पर होटलों और अन्य निजी व्यवसायों के लिए आरक्षित 1 किलोमीटर की दूरी की जगह 500 मीटर पर निर्माण की अनुमति देता है। समुन्द्र तट संरक्षण सीमा में 1 किलोमीटर से कम कर 500 मीटर की दूरी मैनग्रोव, मछुआरों और उनकी आजीविका को प्रभावित करेगा और

शेष पेज 10 पर...

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं कांग्रेस में पारित...

पेज 9 से जारी...

निजी रेत खनन में सहायक होगा।

दलितों पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ जवाबी लड़ाई का संकल्प

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं काँग्रेस देश में दलितों पर बढ़ते अत्याचारों पर अपने चिंताजनक सरोकार व्यक्त करती है। 2014 से जब से आरएसएस–भाजपा शासन केंद्र में है तब से पुलिस के पास आधिकारिक रूप से अत्याचारों के लाखों मामले दर्ज हैं। यहाँ तक कि एक बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज किए बिना रह जाती हैं। पिछले दस सालों के दौरान 4000 से ज्यादा दलित मारे जा चुके हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्डस ब्युरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अत्याचारों पर दर्ज मामलों 2019 में 45, 961 से बढ़कर 2021 में 50, 900 हो गए हैं और यह दिखाता है कि देश में दलितों पर अत्याचार के मामले 11 प्रतिशत बढ़े हैं। देश भर में दलितों पर अत्याचार अबाधित रूप से चालू है, और भाजपा द्वारा शासित राज्यों में दलितों पर अपराध के आँकड़े अधिक मामले दिखाते हैं।

समाज के हाशियाई तबके के खिलाफ अत्याचार के मामलों में बढ़ोतरी, सामूहिक दुष्कर्म और भीड़ हत्या अखंड रूप से भाजपा के दलितों और दमित तबकों के हाशियाई कारण के साथ जुड़ी है। 1989 के अत्याचार अधिनियम के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निवारण को पहले भी किसी भी सरकार द्वारा पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। राज्यों में भाजपा सरकारों ने इन हमलावरों की अगुआई करने वाले अपराधियों को सरंक्षण देने से और आगे चले गए हैं।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं पार्टी काँग्रेस सामाजिक न्याय, वाम और जनतान्त्रिक ताकतों, जन संगठनों और ट्रेड यूनियनों सभी से आह्वान करती है कि दलितों और अन्य कमजोर तबकों पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की काँग्रेस संकल्प लेती है कि इन अत्याचारों के खिलाफ अपना संघर्ष सघन कारेंगें और सरकार से मांग करती है कि दलितों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने के उपाय करे और अत्याचार अधिनियम के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निवारण को मजबूत करे और लागू करने के साथ–साथ सुनिश्चित करे कि दलितों पर हमला करने वाले अपराधियों पर मामले दर्ज किए जाएंगे और उन पर सख्त कार्यवाई की जाएगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दिल्ली में 5 नवंबर को दलितों और आदिवासियों पर हमलों के खिलाफ होने वाले राष्ट्रीय कन्वेन्शन का समर्थन करती है।

नागरिक स्वतंत्रता पर पाबंदियों का विरोध

हम स्वयं में सट्टेबाज वित्तीय पूंजी के साथ जुड़ी हुई एक सांप्रदायिक फासीवादी प्र ति के प्रतिक्रियावादी शासन में रह रहे हैं। इस पड़ाव पर जनतान्त्रिक अधिकारों का बहुत ज्यादा हनन हो रहा है।यह अभिव्यक्ति का अधिकार पहला था जिसका मुंह लगभग बंद कर दिया गया। जनतान्त्रिक अधिकारों कीअनुमति दी गईथी केवल बहुत सीमित हद तक। मतभेदों को अभिव्यक्त करने की अभिव्यक्ति समेत सारे नागरिक अधिकारों पर पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ तक की न्यायपालिका से शिकायतों को अक्सर सहन नहीं किया जाता। पत्रकारों, फिल्म निर्माताओं, कार्यकर्ता सभी बिना किसी मुकदमे के जेल की सजा की चुनौती का सामना कर रहे हैं। उदाहरण ढेरों हैं।

हमें अपनी आजादी चाहते हैं। हम अपने जनतंत्र चाहते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 24 वीं काँग्रेस मांग करती है सारे जनतान्त्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति के अधिकार को कायम किया जाए।

मणिपुर के विशेष श्रेणी दर्जे को कायम किया जाए और लोक सभा में एक सीट बढ़ाने की जरूरत है

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं पार्टी काँग्रेस मणिपुर के विशेष श्रेणी दर्जे को बहाल करने की मांग करती है क्योंकि अन्य राज्यों की तुलना में राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। मणिपुर में दो लोकसभा सीटें हैं। एक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, लेकिन आठ सामान्य विधानसभा क्षेत्र इस अनुसूचित जनजाति आरक्षित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल हैं। चूंकि, भारत के संविधान की शुरुआत के बाद, इन विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं था, हालांकि उन्हें मतदान का अधिकार था। अब, हम मणिपुर राज्य के लिए एक अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मांग करते हैं ताकि मणिपुर का प्रतिनिधित्व तीन सांसदों (दो अनारक्षित और एक अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित) द्वारा किया जा सके। इसके अलावा इसकी जटिल जातीय संरचना को देखते हुए मणिपुर राज्य विधानसभा को द्वि सदनीय होना चाहिए।

राजनीतिक कैदियों को सुनवाई के बिना जेल में रखने के विरोध में प्रस्ताव

केंद्र आरएसएस समर्थित भाजपा सरकार के प्रशासनिक तंत्र का मुख्य आधार बन गया है। देशभर में पूरी तरह से फासीवादी शासन स्थापित करने के लिए, इसने भारत के राजनीतिक–सांस्कृतिक ताने–बाने को अलग करने के अलावा, स्वायत्त संस्थानों को प्रभावित करना और उनसे छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है, चाहे वह शिक्षा, प्रशासन हो या न्यायपालिका हो। विशेष रूप से न्यायपालिका पर नियंत्रण करने के प्रयास हमारे देश, देश की जनता और लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक हैं। जैसे कि, कल, लगभग अप्रत्याशित रूप से, उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के शारीरिक रूप से विकलांग प्रोफेसर डॉ. जी एन साई बाबा और भीमा–कोरेगांव मामले में सभी आरोपों में पांच अन्य को बरी करने के मुंबई उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया।

उच्च न्यायालय के फैसले को निलंबित करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि आमतौर पर आतंकवादी और माओवादी गतिविधियों में दिमाग शारीरिक शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होता है और इस तरह बीमार प्रोफेसर को जेल से बाहर आने और घर में नजरबंद रखने की अनुमति देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायपालिका की ओर से किए गए इस तरह के कृत्यों से संकेत मिलता है कि यह कुछ हद तक सरकार के प्रभाव में हो सकता है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े हमारे संविधान की बुनियादी नींव को कमजोर और नष्ट करने की लगातार कोशिश कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तुलना मुसोलिनी के शासनकाल के दौरान फासीवादी इटली की अदालत के फैसले से की जा सकती है, जब कामरेड अंटोनियों ग्राम्सी को दोषी ठहराया गया था और उनके दिमाग को बीस साल तक रोक कर रखने का आदेश दिया गया था।

इसलिए सभी कम्युनिस्ट, वामपंथी, लोकतांत्रिक और देशभक्त वर्गों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सभी संभावित वास्तविकताओं के मद्देनजर इस तरह के फासीवादी सत्तावादी पहलों का एकजुट होकर विरोध करें। हाल ही में हमारे पार्टी महासचिव ने प्रो. साईं बाबा की पुस्तक 'वाहि डू यू फियर माइ वे' के प्रकाशन के संबंध में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सही रूप से भाग लिया था। किसी के विचार को रोकना अपराध है और हमें राज्य की सत्ता के इन प्रयासों के खिलाफ लड़ना चाहिए। अतः प्रो. साईं बाबा को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। बिना किसी समुचित सुनवाई के जेल में रखे गए सभी राजनीतिक कैदियों भी रिहा किया जाना चाहिए।

मार्क्सवाद के साथ भारतीय संस्कृति के पक्षधर थे फुसकेले

सागरः महेन्द्र फुसकेले मार्क्सवादी थे पर संस्कृति एवं भारतीय परंपरा के संरक्षण के पक्षधर थे। उन्होंने अपने साहित्य में दलित, शोषित व स्त्री की समस्या को उठाया है। यह बात कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉ. सुश्री शरद सिंह ने साहित्यकार महेन्द्र फुसकेले के प्रथम पुण्य स्मरण के अवसर पर वर्णी वाचनालय में बुधवार को कही। यह आयोजन प्रगतिशील लेखक संघ की सागर इकाई ने किया।

इस दौरान शायर मायूस सागरी को महेन्द्र फुसकेले स्मृति साहित्य अलंकरण से सम्मानित किया गया। सागरी ने कक्ष्ण पर आधारित पद को गाकर सुनाया। निरंजना जैन ने सम्मान पत्र का वाचन किया। मुख्य अतिथि सुरेश आचार्य ने मायूस सागरी की काव्य रचना बृजरज पर उन्हें बुंदेलखंड के रसखान बताया।

अध्यक्षता कर रहे डॉ गजाधर सागर ने कहा कि कबीर का फुसकेले के साहित्य पर गहरा प्रभाव है। उन्होंने स्त्री की समस्या को अपने साहित्य में उठाया है।

डॉ. नम्रता फुसकेले ने कहा कि जब वे बच्चों पर रचना कर रहे थे बहुत चिंतित थे कि अब राजा रानी नहीं बच्चे कम्प्यूटर गेम में व्यस्त है, ऐसे में उन्हें सरल पठनीय रचना कैसे लिखें। तब 'घूम री पृथ्वी घूम घूम' पुस्तक लिखी जो सफल रही। प्रलेस के अध्यक्ष टीकाराम त्रिपाठी रुद्र ने फुसकेले के उपन्यासों में स्त्री विमर्श और चेतना का जिक्र किया। उनके शीर्षक बुंदेली के स्वांग गीतों से अनुप्राणित हैं।

कैलाश तिवारी 'विकल' ने फुसकेले की दृष्टि को वैज्ञानिक बताया। पीआर मलैया ने कहा कि उनकी कलम अमानवीयता के खिलाफ चली है।

डॉ. नरेन्द्र जैन ने व्यक्तिगत अनुभव एवं साहित्य सृजन को रेखांकित किया।

इस दौरान उमाकांत मिश्र, पेट्रिस फुसकेले, हरगोविंद विश्व, लक्ष्मी नारायण चौरसिया, डॉ. अनिल जैन, वीरेंद्र प्रधान, वृंदावन राय सरल, पूरन सिंह राजपूत, सतीश रावत, डॉ. नवनीत धगट, आशीष ज्योतिषी, अलबेला तिवारी, मुकेश तिवारी, डॉ लक्ष्मी पांडे, ज्योति झुड़ेले, सुनीला सराफ, दीपा भट्ट, डॉ. मनोज श्रीवास्तव, राजेश पांडे, आशा जैन आदि उपस्थित थे। संचालन डॉ. नलिन जैन व आभार डॉ दिनेश साहू ने माना।

ग्राम पंचायत कुओं में हुये भ्रष्टाचार के खिलाफ वाममोर्चा का धरना

सीधीः वाममोर्चा के आहवान पर जनपद पंचायत रामपुर नैकिन अंतर्गत ग्राम पंचायत कुओं में स्थानीय इकाई द्वारा 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चला धरना प्रदर्शन मुख्य कार्यपालन अधिकारी रामपुर नैकिन के त्वरित निराकरण के बाद 12 अक्टूबर की शाम स्थगित कर दिया गया।

धरना स्थल पर मौजूद ग्राम पंचायत कुआं एवं अन्य गांवों से आयी जनता को संबोधित करते हुए आनंद पांडेय ने कहा कि पूरे प्रदेश में जिस तरह से एक सोची समझी साजिश के तहत पंचायतों की राशि लूटी जा रही है उसमें अकेले एक व्यक्ति दोषी नहीं होता, पूरा तंत्र शामिल है। पंचायतों में आने वाली राशि ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के विकास के लिए आतीं हैं, जनता अपने समस्या के लिए परेशान रहती हैं लेकिन सरपंच निर्भीकता से पैसा हजम कर जाते हैं। बद्री मिश्रा ने कहा कि सरपंच ग्राम पंचायतों में आने वाली विकास कार्यों को कागज में दिखा कर पैसा खा जाते हैं, इसकी जानकारी तमाम उच्च अधिकारियों तक रहती है लेकिन शिकायत के बावजूद कार्यवाही नहीं होती है। इंद्रभान पटेल ने कहा कि पूरे सीधी जिले में रोजगार गारंटी योजना के तहत पंचायतों में मजदूरों की मजदूरी आधी अधूरी देकर शेष मजदूरी हड़प ली जाती है और मजदूर मजदूरी के लिए परेशान रहते हैं। लालबहादुर पटेल ने कहा कि जो लूट पंचायतों में हों रही है उसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और लगातार आंदोलन चलेगा।

उक्त धरने पर बैठे हुववलाल और शेषमणि साहू ने भी संबोधित किया। तत्पश्चात धरना स्थल पर पहुंचकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ज्ञापन लेकर सरपंच के विरुद्ध धारा 40 एवं 92 पंचायत राज अधिनियम के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया और पंचायत में लम्बित अधूरे कार्य सड़क, नाली पर काम तत्काल पूरा करने का आश्वासन दिया। उक्त आंदोलन में सैकड़ों व्यक्ति एवं महिलाओं ने भाग लिया।

एआईएसएफ का उत्तर प्रदेश राज्य सम्मेलन संपन्न

संजय सिंह

शिक्षा ने निजीकरण के खिलाफ आल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के 30वें राज्य सम्मेलन की शुरुआत हुई।

शहर भर में रैली निकाल कर बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। ऑल इण्डिया स्टूडेंट्स फेडरेशन उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य सचिव एवं लखनऊ हाईकोर्ट के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता वाई एस लोहित ने झंडारोहण कर सम्मेलन की विधिवत शुरुआत की। इसके बाद खुला अधिवेशन का सत्र संजय सिंह की अध्यक्षता में शुरू हुआ। खुले अधिवेशन में स्वागताअध्यक्ष रणधीर सिंह सुमन ने आए हुए अतिथियों एवं प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए वर्तमान समय में सरकार के छात्रों के प्रति रवैये को लेकर चिंता जतायी और वर्तमान सरकार किस तरह से अंधविश्वास को फैलाना चाहती हैं जिससे आने वाली पीढ़ियां फिर से गुलामी की ओर चली जाए लगातार फीस वृद्धि और छात्र संघ चुनाव पर भी अपनी बात रखी।

एटक के नेता हेमंत नंदन ओझा ने छात्रों की सफलता में अवसरों की कमी पर चिंता व्यक्त की उन्होंने कहा कि छात्रों के सपने मारे जा रहे हैं नौकरियों पर पाबंदी है। जौनपुर से आए जयप्रकाश सिंह ने कहा कि जेलों में रहकर हमने राजनीति का हुनर सीखा और नारा लगाया की जो चीज सरकारी है वह हमारी है, जिस तरह सरकारी सम्पत्तियों की बेचा जा रहा है उस तरह यह एक नारा मात्र बनकर रह गया है।

लखनऊ उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता वाई एस लोहित ने कहा कि छात्रों को निराशावादी नहीं होना चाहिए और छात्रों को वैज्ञानिक समाजवाद के रास्ते पर चलकर अपने मौलिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए शिक्षा के राष्ट्रीयकरण का मुद्दा उठाना चाहिए। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आनंद दीपायन ने कहा कि किस तरह से उच्च शिक्षा को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, नई शिक्षा नीति से शिक्षा को और कमजोर किया जा रहा है और सरकारी संस्थान किस तरह से बेचे जा रहे हैं, इस माहौल में ऑल इण्डिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की जिम्मेदारी और अधिक हो जाती हैं कि कैसे इनकी नीतियों के खिलाफ छात्र छात्राओं को लामबंद होना होगा पार्टी शिक्षा भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

एआईएसएफ पूर्व महासचिव विश्वजीत कुमार ने कहा कि शिक्षा सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है। नयी शिक्षा नीति इंसान को एक मशीन मात्र में बदलने की नीति है, कोविड–19 के संकट के बाद हमारा नारा "शिक्षा चिकित्सा और रोजगार" पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा ऑल इण्डिया स्टूडेंट्स फेडरेशन देश का पहला संगठन है जिसने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था आज भी समय आ गया है इसी संगठन को आगे आकर देश को बचाने की जिम्मेदारी लेनी होगी प्रदेश की हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में आभियान चलाकर शिक्षा विरोधी नीतियों को बताना होगा, रोजगार के सवाल पर सरकार को घेरना होगा।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव अरविंद राज स्वरूप ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सरकार सिर्फ मजदूर बनाना चाहती है। सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों को इस तरह से परिवर्तित कर दिया है कि सारा औद्योगिक व कृषि का ढांचा निजी हाथों में केंद्रित हो जाए। इसी निजीकरण के कारण महगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है इसी कारण शिक्षा जगत में विद्यार्थी के सामने भविष्य का संकट हो गया है भविष्य में छात्रों को इन्ही नीतियों के खिलाफ लड़ना होगा।

शिवानी मौर्या ने आए हुए अतिथियों एवं प्रतिनिधियों का ऑल इण्डिया स्टूडेंट्स फेडरेशन उत्तर प्रदेश की तरफ से स्वागत किया। संजय सिंह ने कहा कि भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून (बनेगा) को लागू कराने के लिए ऑल इण्डिया स्टूडेंट्स फेडरेशन लगातार आंदोलन कर रही हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 400 प्रतिशत फीस वृद्धि के लिए भी ऑल इण्डिया स्टूडेंट्स फेडरेशन उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का काम कर रही है ऑल इण्डिया स्टूडेंट्स फेडरेशन रोजगार व शिक्षा के मुद्दो को लेकर लगातार आंदोलन कर रही हैं हमारा नारा भी स्टडी एंड स्ट्रगल पढ़ाई लड़ाई साथ साथ इसी संबोधन के साथ खुला अधिवेशन का समापन हुआ।

प्रतिनिधि सत्र का उद्घाटन मुख्य अतिथि ऑल इण्डिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव ने किया।

आगामी विधानसभा सत्र के समय ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन शिक्षा व रोजगार के सवाल को लेकर प्रदर्शन करेगी। इसके पूर्व विभिन्न विश्वविद्यालयों डिग्री कॉलेजों में छात्र आंदोलन शुरू किया जाएगा।

यह विचार व्यक्त करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह ने प्रतिनिधि सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल या डबल इंजन की सरकार सरकारी नौकरियों को समाप्त कर रहा है और समस्त परिसंपत्तियों को अडानी और अंबानी को दे रहे हैं। हम सबको यह लड़ाई लड़नी होगी।

संगठन के प्रदेश सचिव मुजम्मिल जाहिद अली ने कहा कि सरकार ने इंजीनियरिंग व मेडिकल शिक्षा को प्राइवेट हाथों में सौंप कर स्तर विहीन बना दिया है। सम्मेलन को मुनीश कुमार मथुरा, नोमान खान सुल्तानपुर, सतीश जौनपुर, रवि जितेंद्र अलीगढ़, सलमान महाराजगंज, कृष्णा जौनपुर, श्याम सिंह बाराबंकी, उदय भान चित्रकूट, दिवाकर पांडे फतेहपुर, सच्चिदानंद आजमगढ़, इंद्रेश यादव गोंडा, विजय कुमार शुक्ला कानपुर, शिवानी मौर्य लखनऊ, आलोक सिंह अयोध्या, दिव्य मणि फैजाबाद, आदि प्रतिनिधियों ने संबोधित किया। प्रतिनिधि सम्मेलन की अध्यक्षता नोमान खान, मुजम्मिल जाहिद अली, शिवानी मौर्य ने किया। सम्मेलन सुचारू रूप से संचालित करने में रणधीर सिंह 'सुमन' बृजमोहन वर्मा, प्रवीण कुमार, शिवदर्शन वर्मा, विनय कुमार सिंह, महेंद्र यादव आदि का विशेष सहयोग रहा।

अंत में अध्यक्ष–संजय सिंह, सचिव– मुजम्मिल जाहिद अली, उपाध्यक्ष– मुनेश कुमार, रवि, सुफियान, रोहित, सहसचिव–सैफ खान, उदय भान यादव, श्याम सिंह,सतीश, कोषाध्यक्ष– नोमान खान को सर्वसम्मति से चुना गया।

पढ़ाई लड़ाई साथ–साथ..

राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान.. सबको शिक्षा एक समान शिक्षा.. संस्थानों का निजीकरण बंद करो.. आदि गगनभेदी नारों के साथ समापन हुआ।

कामरेड बाल कृष्ण गुप्ता जन्म शताब्दी समारोह: फासीवाद के प्रतिरोध का आह्वान

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2022: वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता और स्वाधीनता सेनानी कामरेड बाल कृष्ण गुप्ता जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनकी स्मृति में प्रति माह आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला की ग्यारहवीं कड़ी के तहत कामरेड बाल कृष्ण गुप्ता जी की वैचारिक और सांगठनिक प्रतिबद्धता के संदर्भ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विगत दिनों विजयवाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन पर केंद्रित विचार विमर्श किया गया।

स्थानीय दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ कर्मचारी नेता आर के तोतरे ने की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मध्य प्रदेश राज्य सचिवमंडल सदस्य सत्यम पांडे ने मुख्य वक्तव्य दिया। शैलेन्द्र शैली ने विषय प्रवर्तन किया। कार्यक्रम का संचालन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला भोपाल के सचिव ए एच सिद्दीकी ने किया।

सत्यम पांडे ने कामरेड बाल कृष्ण गुप्ता की भाकपा के आंदोलनों और विभिन्न कार्यक्रमों में प्रभावकारी भूमिका का उल्लेख करते हुए भाकपा के विगत दिनों विजयवाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में विस्तार से बताया। कामरेड सत्यम पांडे ने भाकपा के संगठन में कायम लोकतंत्र के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने भाकपा के प्रभावकारी राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के विभिन्न पक्षों का उल्लेख किया। इस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों और प्रस्तावों के बारे में विस्तार से बताया। सत्यम पांडे ने कहा कि इस संकट के समय भाकपा की राजनीति स्पष्ट है। समाजवाद ही एकमात्र विकल्प है। हमारा मुकाबला फासीवाद से है। हमें पूंजीवाद, मनुवाद और पितृसत्तात्मक समाज के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़नी होगी।

शैलेन्द्र शैली ने विषय प्रवर्तन करते हुए भाकपा के राष्ट्रीय सम्मेलनों में कामरेड बाल कृष्ण गुप्ता जी के प्रभावकारी प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया तथा इन आयोजनों में कामरेड बाल कृष्ण गुप्ता जी की महत्वपूर्ण भूमिका को याद किया। कामरेड शैलेन्द्र शैली ने कहा कि भाकपा के विजयवाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए गए निर्णय हमारे संघर्ष और प्रतिरोध का प्रेरक दस्तावेज हैं।

आर के तोतरे ने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में कामरेड बाल कृष्ण गुप्ता जी की अपने समय में प्रभावकारी और गरिमामय छवि को याद किया। उन्होंने कहा कि कामरेड बाल कृष्ण गुप्ता अपने आप में एक चलते फिरते आंदोलन थे। कामरेड बाल कृष्ण गुप्ता जी की स्मृति हमें आज भी ऊर्जा प्रदान करती है।

अन्त में भाकपा के जिला भोपाल सचिवमंडल सदस्य कामरेड गुण शेखरन ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भाकपा के जिला सचिवमंडल सदस्य नवाब उद्दीन, मुन्ने खां, एम एल सातपुते, डी आर बंछोर, शिव शंकर मौर्य, रामहर्ष पटेल, ए के परिहार, सचिन श्रीवास्तव सहित विभिन्न गणमान्य नागरिक सम्मिलित हुए।

भारत में उभरता साम्यवाद व पेशावर षडयंत्र मुकदमे

टीकाराम शर्मा

प्रथम विश्व युद्ध के कारण भुखमरी, बेरोजगारी, महामारी, आर्थिक मंदी, महंगाई आदि से भारत में ही नहीं विश्व के अन्य देशों में भी लाखों लोग मौत के शिकार हो गए। सकारात्मक बात यह हुई कि रुस में क्रांति हो गई जिसमें जनता ने जारशाही को उखाड़ फेंका और विश्व में पहली बार मजदूर–किसान की सरकार बन गई। यह विश्व में आशा की एक किरण थी जिसने दबे–कुचले, शोषित, पीड़ित लोगों में, खासकर गुलाम देशों की जनता में यह विश्वास जगा दिया कि वे भी अपने देश में रुस की तरह मजदूर–किसान की सत्ता कायम कर सकते हैं। हमारे देश की स्वतंत्रता के आंदोलन को भी इसने प्रभावित किया। भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से आजाद कराने के लिए देश व विदेश में कई संगठन प्रयासरत थे। इन सबमें महत्वपूर्ण थे–भारत के क्रांतिकारी, जिनमें शामिल थे–भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वामपंथी धड़े के सदस्य, आतंकवादी संगठन, खिलाफत आंदोलन के आंदोलनकारी आदि। इसमें कुछ आंदोलनकारी ऐसे थे जिनका असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद गांधीजी की विचारधारा से मोह भंग हो गया था और वे अक्टूबर क्रांति के बाद वैज्ञानिक समाजवाद की ओर आकृष्ट हुए।

भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का यह पिछली सदी के दूसरे दशक का शुरूआती दौर था। देश के अंदर जगह–जगह मजदूरों व किसानों के आंदोलन तथा हड़तालें हो रही थी। क्रांतिकारी युवक, जो वैज्ञानिक समझ रखते थे, इन आंदोलनों के नेतृत्व कर रहे थे। इस प्रकार देश के विभिन्न भागों में कम्युनिस्ट ग्रुपों का उदय हो रहा था जैसे कि बंबई में डांगे ग्रुप, मद्रास में सिंगारवेलु चेट्टियार ग्रुप, कलकत्ता में मुज्जफर अहमद ग्रुप आदि। अंग्रेज रुसी क्रांति से काफी डर गए थे। अतः उन्होंने भारत के राजनैतिक वातावरण में अक्टूबर क्रांति के विचारों के प्रचार–प्रसार की हर कोशिश या संभावना को शुरूआत में ही कुचलने की नीति बना डाली। हड़तालों, आंदोलनों या सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों को वे शक की नजरों से देखते थे। उन्हें वे रुसी एजेन्ट या बोल्शेविक एजेंट कहते थे। भारत में उभरते साम्यवाद को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने खुफिया विभाग के अंतर्गत एक संगठन बनाया जिसका नाम ही ''बोल्शेविक डिपार्टमेंट'' रखा। उक्त नौजवानों में से बहुतों पर झूठे मुकदमें चलाकर उन्हें कठोर सजाएं दी गई। भारतीय इतिहास में ऐसे मुकदमें कानपुर षडयंत्र केस, पेशावर षडयंत्र मुकदमे व मेरठ षडयंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हैं।

प्रथम विश्वयुद्ध में तुर्की का जर्मनी के साथ गठबंधन था। भारत के मुसलमानों का सहयोग लेने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे तुर्की के प्रति उदारतापूर्वक व्यवहार करें। युद्ध में जर्मनी अंग्रेजों से हार गया और अंग्रेज मुसलमानों को दिया अपना वायदा भूल गए और तुर्की का विभाजन कर दिया। यहीं नहीं, तुर्की के खलीफा जिसको विश्व के मुसलमान अपना धर्मगुरु मानते थे उसका यह पद ही समाप्त कर दिया। इस कारण भारत के मुसलमानों को अंग्रेजों से नफरत हो गई और इस प्रकार खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। सन 1920 में हजारों मुसलमान भारत छोड़ने के लिए यह कह कर तैयार हो गए कि अंग्रेजी राज में यह देश उनके रहने लायक नहीं रह गया है। अफगानिस्तान के अमीर अमानतुल्ला खान के आश्वासन पर वहां बसने के इरादे से देश छोड़ गए। भारत सरकार ने इसमें किसी प्रकार का कोई दखल नहीं दिया बल्कि उनको सीमा पार करवाने में मदद की। भारत के इतिहास में यह हिजरत आंदोलन के नाम से जाना जाता है।

इन मुहाजिरों में से कुछ नौजवान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तुर्की की सेना में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान से तुर्की की ओर निकल गए। इनके पास न कोई पासपोर्ट था न वीजा न ही कोई अन्य दस्तावेज। दुर्गम पहाड़ियों, नदियों तथा अत्यंत विषम इलाकों को पार कर ये नौजवान रुस के इलाके में पहुंच गए जहां हन्हें रुस की लाल सेना ने गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने रुसी सेना को अपना उद्देश्य बताते हुए यकीन दिलाया कि वे भारत के राष्ट्रवादी नौजवान है, रुस के दुश्मन नहीं। सेना ने उन्हें दो नावें मुहैया करवा दी ताकि वे आमू दरिया पार कर सकें। वे नदी में कुछ दूर ही गए थे कि प्रतिक्रांतिकारी सेना ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें एक लाइन से खड़ा किया गया और गोलियों से एक–एक को मारने वाले ही थे कि–सौभाग्यवश नजदीक में ही लाल सेना की मौजूदगी की आहट मिली जिससे प्रति प्रतिक्रांतिकारी भाग खड़े हुए और ये लोग बच गए।

इस बीच लाल सेना की एक टुकड़ी वहां आ गई और ये लोग पकड़ लिए गए परंतु वे सेना को यह विश्वास दिलाने में सफल रहे कि वे रुस के दुश्मन नहीं हैं। उसी समय प्रतिक्रांतिकारियों ने लाल सेना की इस टुकड़ी पर हमला कर दिया जिसमें इन नौजवानों ने लाल सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस हमले को नाकाम कर दिया। यह समाचार जब जनता को मिला तो इन नौजवानों को वीरों जैसा सम्मान दिया गया। उन्हें ताशकंद व मॉस्को भेजा गया जहां वे बोल्शेविकों के संपर्क में आए और कम्युनिस्ट बन गए।

इन्होंने ताशकंद तथा मॉस्को में राजनैतिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसका परिणाम यह हुआ के ये लोग पान–इस्लामिक उन्माद से मुक्त हो गए। यही नौजवान थे जिन्होंने 1920 में ताशकंद में ''प्रवासी'' भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये सभी नौजवान मुसलमान थे। अब वे देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के मकसद से अलग–अलग झुंडों में स्वदेश लौटने लगे। रास्ते की कठिन बाधाओं को पार करते हुए, कुछ तो सरहद पर ही पकड़े गए, कुछ बाद में। पकड़े गए अभियुक्तों पर देशद्रोह के मुकदमे चले। उन सब पर एक ही आरोप था कि वे ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलटने की साजिश कर रहे थे। मुकदमों के लिए पेशावर शहर इसलिए चुना गया कि अंग्रेजी राज को डगमगाने के लिए बोल्शेविक नीतियों के संबंध में खबरें गढ़ना आसान होगा तथा अभियुक्तों को ज्यूरी सिस्टम का लाभ नहीं मिलेगा।

इस प्रकार पहला मुकदमा ब्रिटिश ताज बनाम मोहम्मद अकबर कुरैशी एवं अन्य (1921) था जिसमें मोहम्मद अकबर खान उर्फ मोहम्मद अकबर कुरैशी उम्र 26 वर्ष, बहादुर 18 वर्ष और हाफिजुल्ला खान उम्र 52 वर्ष, तीन अभियुक्त थे जिन पर आरोप था कि वे ब्रिटिश भारत पर उसकी संप्रभुता से वंचित करने के लिए ब्रिटिश बादशाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कथित साजिश रच रहे थे। बहादुर तिब्बत का रहने वाला था जिसे भारत व अफगानिस्तान के बीच कबीलाई व पहाड़ी इलाके की अच्छी जानकारी थी, इस कारण अकबर खान ने उसे अपने नौकर के रूप में रखा। हाफिजुल्ला खान अकबर खान के पिता थे जो एक समय नार्थ–वेस्ट फ्रंटियर प्रान्त की सीआईडी के लिए स्थायी मुखबिर के रूप में काम कर चुके थे। 25 सितंबर 1921 को मोहम्मद अकबर व बहादुर को पेशावर सीमा पर गिरफ्तार कर लिया और 28 सितंबर को हाफिजुल्ला खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अक्टूबर 1921 को वहां के चीफ कमिश्नर की स्वीकृति के साथ ही कानूनी कार्यवाही शुरू की गई। 31 मई 1922 को फैसला सुनाया गया जिसमें अकबर खान व बहादुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 121ए के तहत क्रमशः 3 वर्ष व 1 वर्ष की कठोर कारागार की सजा सुनाई गई जब कि हाफिजुल्ला खान को बरी कर जेल से रिहा कर दिया गयां

दूसरा मुकदमा ब्रिटिश ताज बनाम मोहम्मद अकबर, खान एवं अन्य (1923) के नाम से था। इसमें अकबर खान, जिन्हें पहले के केस में 3 वर्ष की सजा सुनई गई थी तथा मोहम्मद हसन व गुलाम महमूद थे। आरोप था कि अकबर खान ने किसी गोपनीय तरीके से जेल से बाहर कुछ पत्र भेजें। पत्र जिनको मिलने थे वह फ्रंटियर प्रान्त के बाहर के लोग थे और उनका संबंध समरकंद क्रांतिकारी समूह से था। जुलाई 1922 को दो लोग–मोहम्मद हसन व गुलाम महबूत पकड़े गए जिनके पास कथित तौर पर भेजे गए पत्र बरामद हो गए। इन दोनों को सह–अभियुक्त बनाया गया। योजना के अनुसार, अकबर खान नार्थ–वेस्ट फ्रंटियर प्रान्त के कबीलाई इलाके में एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर भारत में वितरण के लिए एक समाचार पत्र और पुस्तिकाएं प्रकाशित करना चाहते थे परंतु इसमें सफल होने से पहले ही पकड़े गए। इस केस की सुनवाई भी वही जज कर रहे थे जिसने पहले मुकदमे में उन्हें 3 वर्ष की कठार कारावास की सजा सुनाई थी। 27 अप्रैल 1923 का फैसला सुनाया गया जिसमें मोहम्मद अकबर खान को तीन महीने का एकान्त कारावास समेत 7 वर्ष का कठोर कारावास, यह सजा पहली सजा के पूरी होने के बाद शुरू होने की बात कही गई। सह – अभियुक्तों को तीन महीने का एकान्त कारावास समेत 5 वर्ष का कठोर कारावास की सजा।

तीसरा पेशावर षडयंत्र मुकदमा (ब्रिटिश राज बनाम अकबर शाह एवं अन्य सात) 7 मार्च 1923 को जांच मजिस्ट्रेट के सामने शुरू और 4 अप्रैल 1923 को सेशन कोर्ट के सुपुर्द कर दिया गया। आरोप था कि अभियुक्तों ने भारत सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारत से बाहर विभिन्न स्थानों पर षडयंत्र रचे और वे इस उद्देश्य से भारत आए हैं कि उन्होंने उन स्थानों पर जो क्रांतिकारी शिक्षण एव निर्देश मिले हैं उनको अमलीजामा पहनाया जा सके। अभियुक्तों में से चार–रफीक अहमद, फिरोजुद्दीन मन्सूर, अब्दुल मजीद व हबीब अहमद पामीर–चित्राल सीमा पर पकड़े गए जबकि तीन अभियुक्त–सुल्तान मोहम्मद, अब्दुल कादर और फिदा अली एक हफ्ते बाद यहां पहुंचे और उन्हें 23 नवंबर 1923 को भारतीय पॉलिटिकल एजेंट के सामने पेश किया गया। उसके बाद भारत भेज कर गिरफ्तार किया गया। अकबर शाह स्वेच्छा से नौशेरा के सहायक कमिशनर के सामने पेश हुए और गिरफ्तार कर लिए गए। अंतिम अभियुक्त गौहर रहमान को भी भारत लौटते ही 1 मार्च 1923 को गिरफ्तार कर लिया गया। फिदा अली सरकारी गवाह बन गया। 18 अप्रैल 1923 को फैसला सुनाया गया जिसमें अकबर शाह व गौहर खान को 2 वर्ष की कठोर कारावास, फिरोजुद्दीन मन्सूर, अब्दुल मजीद, हबीब अहमद, सुल्तान मुहम्मद और रफीक अहमद को एक–एक वर्ष का कठोर कारावास की सजा तथा अब्दुल कादिर को रिहाई मिली।

चौथा मुकदमा ब्रिटिश ताज बनाम मोहम्मद शफीक के नाम से जाना जाता है। जज के सामने दिए गए अपने बयान के अनुसार मोहम्मद शफीक ओकारा जिला पेशावर का रहने वाला था, जो वहां सिंचाई विभाग में क्लर्क के पद पर कार्यरत था। वह मई 1919 में काबुल पहुंचा और वहां भरत की अस्थाई सरकार का सदस्य बना। कुछ समय बाद वह ताशकंद पहुंचा और 7 अक्टूबर 1920 को प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनी, वह उसका सचिव चुना गया। यहां आने के दो महीने बाद उसने जमींदारी (यानी किसान) नाम के फारसी व उर्दू में एक पत्र का संपादन किया जिसका मकसद भारतीय मजदूरों में जोश भरना था उन्हें रुसी क्रांति के तौर–तरीकों से अवगत कराना था। इसका केवल एक ही अंक निकल सका था। इसके बाद वह आचार्य के साथ मॉस्को पहुंचा जहां कॉमिन्टर्न की दूसरी कांग्रेस हो रही थी जिसमें वह विजिटर्स कार्ड पर शामिल हुआ। बाद में वह ताशकंद स्कूल में शामिल हुआ परंतु सन् 1921 में गर्मियों में यह स्कूल

शेष पेज 15 पर...

पुस्तक समीक्षा

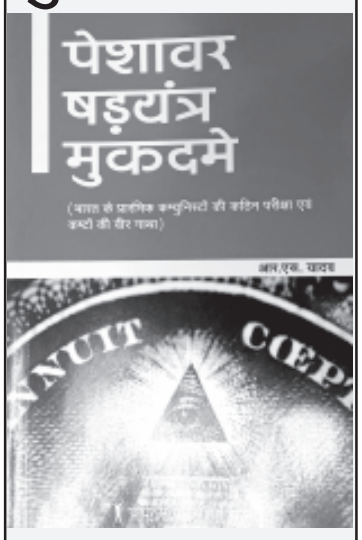

पुस्तक का नाम: पेशावर षड़यंत्र मुकदमे
लेखक: आर.एस. यादव
मूल्य: 115/– रुपए
पृष्ठ संख्या: 73
प्रकाशक: पी.पी.एच.
वर्ष: जुलाई 2022

सज्जाद जहीर और तरक्कीपसंद तहरीक

जाहिद खान

मौजूदा दौर में हमारे देश के अंदर कई लेखक संगठन काम कर रहे हैं। इन लेखक संगठनों में उन संगठनों की अलग से शनाख्त की जा सकती है, जो अवाम के बुनियादी मुद्दों को अहमियत के साथ उठाते हैं। इस संगठनों से जुड़े लेखक न सिर्फ अपने लेखन में जनता के सवालों को केन्द्र में रखते हैं, बल्कि सरकारों से उनकी तमाम मामलों में जवाबदेही मांगने से भी किनारा नहीं करते। ऐसा कई मर्तबा हुआ है, जब इन लेखक संगठनों ने अनेक मामलों में अवाम की रहनुमाई की। उन्हें एक नया रास्ता दिखलाया। प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ और 'जन संस्कृति मंच' इन संगठनों में अव्वल नंबर पर हैं। यह सभी लेखक संगठन प्रगतिशील आंदोलन की उपज हैं। आजादी के पहले चले प्रगतिशील आंदोलन का कभी खूब दौर–दौरा था। प्रगतिशील आंदोलन के उस वक्त केंद्र बिंदु थे राइटर, जर्नलिस्ट, एडिटर और फ्रीडम फाइटर सज्जाद जहीर। तरक्कीपसंद तहरीक के वे रूहे रवां थे। उन्होंने अपनी सारी जिन्दगी प्रगतिशील मूल्यों को स्थापित करने और अवाम को वाजिब हक दिलाने, समाजी इंसाफ की लड़ाई लड़ने में गुजार दी। वे मुल्क के लाखों पसमांदा इंसानों में ऐसा शऊर पैदा करना चाहते थे, जो उन्हें सामाजिक, आर्थिक शोषण और सियासी गुलामी से निजात दिलाने में मददगार हो सके। दोस्तो में 'बन्ने भाई' के नाम से मकबूल सज्जाद जहीर सांस्कृतिक आंदोलन के जरिए अवाम में चेतना जगाना चाहते थे। वह मानते थे कि अवाम में सांस्कृतिक सजगता और सियासी, समाजी चेतना पैदा होगी, तो वह खुद अपनी आजादी, हक और हुकूक के लिए उठ खड़े होंगे। यही नहीं उनकी यह सोच भी थी कि हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में लेखक, संस्कृतिकर्मी ही अहम भूमिका निभा सकते हैं।

सज्जाद जहीर की यह क्रांतिकारी सोच यकायक नहीं बनी थी, बल्कि इसमें उस हंगामाखेज दौर का बड़ा रोल था, जिसमें उनकी तर्बीयत हुई थी। कानूनी तालीम के वास्ते साल 1927 से 1935 तक जहीर का लंदन में कियाम रहा। 1930 से 1935 तक का दौर, दुनियावी ऐतबार से बदलाव का जमाना था। जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर जॉर्जी दिमित्रोव के मुकदमे, फ्रांस के मजदूरों की बेदारी और ऑस्ट्रिया की नाकामयाब मजदूर क्रांति से सारी दुनिया में क्रांति के एक नये युग का आगाज हुआ। 1933 में फ्रांसीसी साहित्यकार हेनरी बारबूस की कोशिशों से फ्रांस में लेखक, कलाकारों का फासिज्म के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा 'वर्ल्ड कान्फ्रेंस ऑफ राइटर्स फॉर दि डिफेन्स ऑफ कल्चर' बना। जो आगे चलकर पापुलर फ्रंट (जन मोर्चा) के तौर पर तब्दील हो गया। इस संयुक्त मोर्चे में मैक्सिम गोर्की, रोम्या रोलां, आंद्रे मालरो, टॉमस मान, वाल्डो फ्रेंक, मारसल, आंद्रे जीद, आरांगो जैसे विश्वविख्यात साहित्यकार शामिल थे। लेखक, कलाकारों के इस मोर्चे को जनता के बीच बड़ी हिमायत हासिल थी। विश्व परिदृश्य में तेजी से घट रही इन सब घटनाओं ने सज्जाद जहीर को काफी मुतअस्सिर किया। जिसका सबब, साल 1935 में लंदन में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना थी। उन्होंने अपने चंद तरक्कीपसंद दोस्तों के साथ यहां प्रगतिशील लेखक संघ की दागबेल डाली। आगे चलकर सज्जाद जहीर ने तरक्कीपसंद तहरीक को आलमी तहरीक का हिस्सा बनाया। स्पेन के फासिस्ट विरोधी संघर्ष में सहभागिता के साथ–साथ उन्होंने साल 1935 में आंद्रे गीडे व मेलरौक्स द्वारा आयोजित विश्व बुद्धिजीवी सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। अपनी जिंदगी को एक नयी राह देने और एक खास मकसद और इरादे के साथ सज्जाद जहीर ने साल 1936 में लंदन छोड़ा। भारत वापस लौटते ही उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन की तैयारियां शुरू कर दीं। 'प्रगतिशील लेखक संघ' के घोषणा–पत्र पर उन्होंने भारतीय भाषाओं के तमाम बड़े लेखकों से विमर्श किया। प्रगतिशील लेखक संघ की पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई। कॉफ्रेंस की सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की।

सज्जाद जहीर प्रगतिशील लेखक संघ के पहले महासचिव चुने गए और 1949 तक उन्होंने यह दायित्व संभाला। बन्ने भाई के व्यक्तित्व और दृष्टिसम्पन्न परिकल्पना की ही वजह से तरक्कीपसंद तहरीक आगे चलकर हिन्दुस्तान की आजादी की तहरीक बन गई। मुल्क के तमाम अदीब, कलाकार और संस्कृतिकर्मी इस आंदोलन के साथ आ गए। साल 1942 से 1947 तक का दौर प्रगतिशील लेखक संघ के आंदोलन का सुनहरा दौर था। यह आंदोलन आहिस्ता–आहिस्ता देश की सारी भाषाओं में फैला। इन सांस्कृतिक आंदोलनों का आखिरी मकसद मुल्क की आजादी था। शुरुआती दिनों में सज्जाद जहीर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी रहे। इलाहाबाद शहर कांग्रेस कमेटी के महासचिव होकर उन्होंने पं.जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया। आगे चलकर अखिल भारतीय कांग्रेस के मेम्बर चुने गए। कांग्रेस के मुख्तलिफ महकमों खासतौर पर विदेशी मामलों और मुस्लिम जनसंपर्क से भी वे जुड़े रहे। कांग्रेस में काम करने के दौरान उनका वास्ता उस वक्त अंडरग्राउण्ड चल रहे कम्युनिस्ट लीडर पीसी जोशी से हुआ। कामरेड जोशी के साम्यवादी विचारों से वह बेहद प्रभावित हुए। बाद में कांग्रेस छोड़कर, वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश इकाई के सचिव भी रहे। उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी अंग्रेज सरकार के कोप से बचने की खातिर अंडरग्राउण्ड रहकर काम करती थी। साल 1942 में अंग्रेजी हुकूमत ने कम्युनिस्ट पार्टी से पाबंदी हटा ली, तो सज्जाद जहीर अपने काम में पहले से भी ज्यादा जी–जान और जोश के साथ जुट गए।

अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लिखने

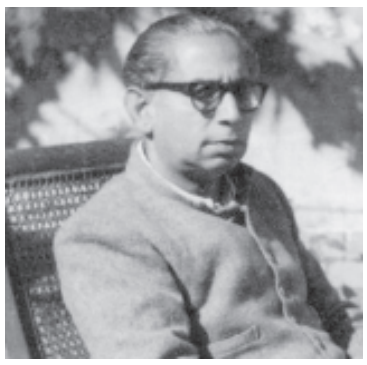

और तकरीर करने के जुर्म में सज्जाद जहीर को तीन मर्तबा जेल हुई। बावजूद इसके वह अलग–अलग नामों से अखबारों के लिए लगातार लिखते रहे। कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार 'कौमी जंग' और 'नया जमाना' अखबार में सज्जाद जहीर ने प्रधान सम्पादक की हैसियत से काम किया। लंदन में जर्नलिज्म की पढ़ाई, संपादकीय सूझ–बूझ और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि की बदौलत इन पत्रों ने जल्द ही लोगों के बीच अपनी पहचान बना ली। ये पत्र हिन्दुस्तान के प्रगतिशील लेखकों की आवाज बन गए। इस आंदोलन में लेखकों का शामिल होना प्रगतिशीलता की पहचान हो गई। प्रगतिशील आन्दोलन ने जहां धार्मिक अंधविश्वास, जातिवाद और हर तरह की धर्माधता की मुखालिफत की, वहीं साम्राज्यवादी, सामंतशाही व आंतरिक सामाजिक रूढ़ियों रूपी दुश्मनों से भी टक्कर ली। एक समय ऐसा भी आया, जब उर्दू के सभी नामवर साहित्यकार प्रगतिशील लेखक संघ के बैनर तले आ गए थे। फैज अहमद फैज, अली सरदार जाफरी, मजाज, कृश्न चंदर, ख्वाजा अहमद अब्बास, कैफी आजमी, मजरूह सुल्तानपुरी, इस्मत चुगताई, महेन्द्रनाथ, साहिर लुधियानवी, हसरत मोहानी, उपेन्द्रनाथ अश्क, सिब्ते हसन, डॉ. रशीद जहां, जोश मलीहाबादी, फिराक गोरखपुरी, राजिंदर सिंह बेदी, सागर निजामी, वामिक जौनपुरी और मखदूम जैसे आला नाम तरक्कीपसंद तहरीक के हमनवां, हमसफर थे। इनकी कलम ने मुल्क में आजादी के हक में समां बना दिया। यह वह दौर था, जब तरक्कीपसंद लेखकों को नये दौर का रहनुमा समझा जाता था। यहां तक कि तरक्कीपसंद तहरीक को जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, रवीन्द्रनाथ टैगोर, अल्लामा इकबाल, खान अब्दुल गफ्फार खान, प्रेमचंद, वल्लथोल जैसी हस्तियों की सरपरस्ती हासिल थी। वे भी इन लेखकों के लेखन एवं काम से बेहद मुतअस्सिर और मुतमईन थे।

मुल्क की तक्सीम के बाद सज्जाद जहीर को कम्युनिस्ट पार्टी के फैसले की वजह से कुछ समय के लिए पार्टी को संगठित करने के लिहाज से पाकिस्तान जाना पड़ा। पाकिस्तान में उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान का महासचिव चुन लिया गया। वहां उन्होंने विद्यार्थियों, मजदूरों और ट्रेड यूनियन के संगठन का जिम्मा संभाला। मगर पाकिस्तान में भी हालात उनके मनमाफिक नहीं थे। उस दौर की कट्टरपंथी सरकार के चलते सज्जाद जहीर ने वहां भी अंडरग्राउण्ड रहकर काम किया। कुछ अरसे बाद ही हुकूमत–ए–पाकिस्तान ने 'रावलपिंडी साजिश' केस में उन्हें फैज अहमद फैज के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे और सजा के दरमियान सज्जाद जहीर ने हैदराबाद, सिंध, लाहौर, मच्छ और कोयटा की जेलों में जुल्मो–सितम सहते हुए पांच साल गुजारे। अदालत में सरकारी वकील ने उन्हें सजा–ए–मौत देने की मांग की। भारत सरकार के अभियान और सारी दुनिया के बुद्धिजीवियों, लेखकों, कलाकारों के दबाव में पाकिस्तान सरकार को आखिरकार उन्हें रिहा करना पड़ा। रिहाई के बाद सज्जाद जहीर हिंदुस्तान लौटे, तो उन्होंने एक बार फिर प्रगतिशील लेखक संघ की गतिविधियां तेज कर दीं। दुनिया में जाति, रंग, नस्लवाद, साम्राज्यवाद के खतरे अब भी बरकरार थे। साल भर के अंदर ही सज्जाद जहीर ने डॉ. मुल्कराज आनंद के साथ रूस में अफ्रो–एशियाई साहित्यकारों की पहली कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जो अफ्रो–एशियाई लेखकों का जबर्दस्त आंदोलन साबित हुआ। समाजवाद में गहरा अकीदा रखने वाले सज्जाद जहीर फासिस्टों को छिपा हुआ साम्राज्यवादी मानते थे। यूं तो सज्जाद जहीर की जिंदगी का ज्यादातर वक्त संगठनात्मक कार्यों में ही बीता। फिर भी साहित्यिक लेखन के साथ–साथ वह देश–विदेश की पत्र–पत्रिकाओं में सामाजिक और राजनैतिक मसलों पर लगातार लिखते रहे। साल 1935 में छपे चर्चित कहानी संग्रह 'अंगारे' में सज्जाद जहीर की भी कहानी शामिल थी। समाजी और सियासी ऐतबार से यह संग्रह उस समय काफी मशहूर हुआ। हुकूमत की पाबंदी के साथ–साथ इस किताब को अपने ही मुल्क के प्रतिक्रियावादियों और संकीर्णतावादियों की तंगनजरी का सामना करना पड़ा। आलम यह था कि उस वक्ढत इस संग्रह के लेखकों को 'अंगारे' के लेखक के नाम से पुकारा जाता था।

साल 1935 में ही पेरिस में लिखा गया सज्जाद जहीर का छोटा उपन्यास 'लंदन की एक रात' जैसा कि नाम से जाहिर है सिर्फ एक रात का तब्सिरा है। अनोखे शिल्प का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इसमें मुल्क की आजादी की चाह लिए परदेस में रह रहे नौजवानों के जज्बात का शानदार चित्रण किया है। 'पिघला नीलम' सज्जाद जहीर की नज्मों का संग्रह है, जो उन्होंने जिंदगी के आखिढरी दौर में लिखा। सज्जाद जहीर का अहम अदबी शाहकार 'रौशनाई' है। यह किताब उन्होंने पाकिस्तान की जेलों में कैद की हालत में लिखी थी। अदबी हल्कों में इसे प्रगतिशील लेखक संघ का प्रमाणिक इतिहास माना जाता है। यह किताब, अकेले 'अंजुमन तरक्कीपसंद मुसन्निफ' का ही दस्तावेज नहीं है, बल्कि आजादी की जद्दोजहद के पूरे हंगामाखेज दौर और उस वक्त के सियासी, समाजी हालात का भी खाका पेश करती है। साथ ही इसमें सज्जाद जहीर की आलोचना की प्रतिभा भी देखी जा सकती है। इस किताब में अदब और ललित कलाओं के नुक्तों पर तो रोशनी डाली ही गई है, प्रगतिशील साहित्य की बुनियादी समस्याओं, बहसों, संवाद, कॉन्फ्रेंस, उद्देश्यों को भी कलमबद्ध किया गया है। बकौल रौशनाई के हिन्दी अनुवादक जानकी प्रसाद शर्मा, ''रौशनाई में इतिहास, संस्मरण और शेरो अदब की समीक्षा के साथ–साथ मार्क्सवादी सिद्धांत निरूपण की धाराएं एक दूसरे में पैबस्त नजर आती हैं.'' सज्जाद जहीर ने ईरान के अजीम गजलगो हाफिज शिराजी की शायरी पर भी एक शोध प्रबंध 'जिक्र–ए–हाफिज' लिखा है। 'तरक्कीपसंद तहरीक, अदब और सज्जाद जहीर', 'मजामीन–ए–सज्जाद जहीर', 'उर्दू–हिन्दी हिन्दुस्तानी', 'उर्दू का हाल और मुस्तकबिल' उनकी दीगर किताबें हैं। 13 सितंबर, 1973 को अल्माअता (सोवियत संघ) में (जो कि अब कजाकिस्तान में पड़ता है।) अचानक दिल का दौरा पड़ने से सज्जाद जहीर का निधन हो गया। तरक्कीपसंद तहरीक की जब भी बात होगी, सज्जाद जहीर और उनके इंकलाबी कामों को जरूर याद किया जाएगा।

चांपा एटक का द्वितीय जिला सम्मेलन संपन्न

चांपा, 30 अक्टूबर 2022: जांजगीर– चांपा जिला ट्रेड युनियन कौंसिल एटक का द्वितीय जिला सम्मेलन कोसा, कांसा, कंचन की नगरी चांपा नगर के गांधी भवन में कामरेड गुरूदास दास गुप्ता सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ राज्य एटक के महासचिव हरिनाथ सिंह जी एवं भाकपा बिलासपुर जिला सचिव पवन शर्मा जी के मुख्य आथित्य में सम्पन्न हुई।

जिला एटक सम्मेलन कार्यक्रम की पहली कड़ी में सुबह 10.30 बजे ऑटो स्टैण्ड रेलवे स्टेशन चांपा से जिला एटक के बैनर तले सम्मेलन में शामिल होने आये हुए विभिन्न जन संगठनों छत्तीसगढ़ ऑटो चालक संघ एटक, छत्तीसगढ़ न्यू प्रगतिशील आंगनबाडी कर्मचारी एवं सहायिका संघ, छत्तीसगढ़ पेपर मिल श्रमिक संघ बिरगहनी, मडवा ताप विद्युत कामगार एवं भू–विस्थापित श्रमिक संघ, छत्तीसगढ़ मनरेगा मजदूर संघ के श्रमिकों के द्वारा विशाल रैली चांपा नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए गांधी भवन, रामबांधा तालाब के पास पहुँची। सर्वप्रथम हरिनाथ सिंह जी के द्वारा झण्डोत्तोलन किया गया तत्पश्चात् आंदोलन के दौरान शहीद हुए मजदूरों व मजदूर जन नेताओं की वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित की गयी।

जिला सम्मेलन में विभिन्न जन संगठनों के शामिल साथियों को ओमशरण सिंह क्षत्रिय के द्वारा क्रांतिकारी अभिवादन एवं धन्यवाद आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में आये मुख्य अतिथियों एवं मंचस्थ अध्यक्षमण्डल का स्वागत एवं सम्मान में आशा सोनी के द्वारा लाल गमछा भेंट कर किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में प्रदेश एटक महासचिव ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार एवं राज्य में राज्य सरकार के द्वारा किसान मजदूर विरोधी नीतियाँ अपनायी जा रही है। जिसके विरोध में संयुक्त ट्रेड युनियनों के मंच के द्वारा समय–समय पर संयुक्त रूप से आंदोलन और कार्यवाही किए जा रहे है। उन्होंने शहीद और बलिदानों के बुनियाद पर खड़ा देश के मजदूर वर्ग का एक मजबूत स्तम्भ है, जिसकी स्थापना ब्रिटिश काल के दौरान 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मान्यवर लाला लाजपत राय जी की अध्यक्षता में हुई है। आजादी के पश्चात् देश के मजदूरों के द्वारा किये गये लंबे संघर्ष और दिये गए अनेको बलिदानों के कारण अनेकों श्रम कानून बनाये गये। जिसमें भविष्य निधी, बोनस एवं सामाजिक सुरक्षा जैसे बुनियादी अधिकारों को प्राप्त करने के यह मजदूर हकदार हुए। एटक का मुख्य उद्देश्य किसान और मजदूरों की कमाई को लुटने वालों के विरुद्ध अनवरत संघर्ष जारी रखना एवं मेहनतकशों को सुरक्षा प्रदान करना।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए बिलासपुर जिला भाकपा के जिला सचिव पवन शर्मा ने कहा कि लाल झण्डा ही एकमात्र उपाय है जो देश में समानता का अधिकार दिलाने के लिए पूरे भारत वर्ष में एकमात्र लड़ने वाले जन संगठन लाल झण्डा एवं एटक है जो देश के मजदूरों, गरीबो की लड़ाई लड़ती है। हम सभी मजदूरों को आज एक बात अपने दिल में गांठ बांध लेनी चाहिए कि हमारी एकता ही हमारी मजबूती है। हम सभी जनसंगठनों को एक साथ मिलकर एकजुट होना ही पडेगा, क्योंकि अभी की जो पूंजीवादी सरकारे केन्द्र की हो या राज्य की सभी मजदूर विरोधी श्रम विरोधी काम कर रही हैं। कार्यक्रम सत्र को आगे बढ़ाते हुए नसीम बानो के द्वारा जिला कौंसिल का प्रतिवेदन पढ़ा गया। सुधीर यादव के द्वारा कार्यक्रम में मंच संचालन किया गया एवं जिला एटक सम्मेलन में संयोजन व व्यवस्थापन कार्य में रघुनंदन सोनी, राजेश शुक्ला, मिर्जा असलम बेग, ललित महंत, महेश महंत, अजय रात्रे, श्याम कुमार बरेठ, अरविंद अनंत, लखन साहू, आशा सोनी, रानू वैष्णव, अनुराधा शुक्ला आदि साथियों की मुख्य भुमिका रही।

नवनिर्वाचित पदाधिकारी

जिलाध्यक्ष–सुधीर यादव, उपाध्यक्ष–मिर्जा असलम बेग, राम खिलावन राठौर, नसीम बानो, आशा सोनी, भारती देवी साहू, अनंदराम साहू, भुनेश्वर सिंह कवर।

जिला सचिव–राजेश शुक्ला, सहसचिव–ओमशरण सिंह क्षत्रिय, कोषाध्यक्ष–रघुनंदन सोनी, कार्यालय सचिव–जानकी पटेल।

कार्यकारिणी सदस्य – महेश महंत, अजय रात्रे, ललित महंत, अनुराधा शुक्ला, रानु वैष्णव, हेमलता श्रीवास, श्याम कुमार बरेठ, गौरव साहू, अमृत साहू, तिलकराम साहू, धर्मेन्द्र राठौर, निर्मला कंवर सर्वसम्मति से चुनें गए।

पी.पी.एच. पब्लिकेशन

पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	मूल्य
1. मध्यकाल में औरतों की बलियां और हत्याएं	केशव चंद्र	120.00
2. आरक्षण किसके लिए?	पी.एस. कृष्णन	30.00
3. लाल झंडे का इतिहास	अनिल राजिमवाले	50.00
4. साम्प्रदायिक इतिहास और राम की अयोध्या	रामशरण शर्मा	15.00
5. भारत में राज्य की उत्पत्ति	रामशरण शर्मा	50.00
6. मुक्तिबोध की संकलित प्रगतिवादी रचनाएं	राजेन्द्र राजन	200.00
7. राहुल निबंधावली–साहित्य	राहुल सांकृत्यायन	90.00
8. हिन्दू पहचान की खोज	डी.एन. झा	100.00
9. हम अच्छे कम्युनिस्ट कैसे बनें	ल्यू शाओ ची	50.00
10. विवाद ग्रस्त मस्जिद–एक ऐतिहासिक छानबीन	सुशील श्रीवास्तव	75.00
11. मजूरी, दाम और मुनाफा	कार्ल मार्क्स	25.00
12. भगत सिंह की राह पर	ए.बी. बर्धन	15.00
13. जन–जातियों के धार्मिक विश्वास	...	330.00
		430.00 (एचबी)
14. प्राचीन भारत में भौतिकवाद	देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय	200.00
15. विवेकानंद सामाजिक राजनीतक विचार	विनोय के. राय	75.00
16. हिंदू राष्ट्रवाद और उसका यथार्थ	कृष्णा झा	65.00
17. राजनैतिक अर्थशास्त्र और विश्व आर्थिक संकट	अनिल राजिमवाले	65.00
		100.00 (एचबी)
18. मार्क्सवादी डाइलेक्टिक्स की मूल समस्याएं	अनिल राजिमवाले	75.00
19. पाप और विज्ञान	डाइसन कार्टन	50.00
20. मैं नास्तिक क्यों हूं	विपिन चन्द्र	30.00
21. भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण	भगवत शरण उपाध्याय	100.00
22. शिवाजी कौन थे?	गोविन्द पानसरे	60.00
23. मार्क्सवाद क्या है?	एमिल बर्न्स	40.00
24. कार्ल मार्क्स–भारत संबंधी लेख	कार्ल मार्क्स	80.00
25. वर्ग जाति आरक्षण और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष	ए.बी. बर्धन	60.00
		125.00 एचबी
26. भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम–1857–59	कार्ल मार्क्स	200.00
27. प्राचीन भारत में जनजीवन	एस.आर. भट	30.00
28. भारत आदिम साम्यवाद से दास प्रथा तक का इतिहास	श्रीपाद अमृत डांगे	200.00
29. मनुष्य और समाज	.....	170.00
30. भारतीय विवाह संस्था का इतिहास	विश्वनाथ काशीनाथ राजवडे	85.00
31. बाल हृदय की गहराइयां	वसीली सुखोम्लीन्स्की	125.00
32. मां	माक्सिम गोर्की	200.00
33. रामराज्य और मार्क्सवाद	राहुल सांस्कृत्यायन	60.00
34. राज्य और क्रान्ति	लेनिन	70.00
35. साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था	लेनिन	50.00
36. कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र	मार्क्स, एंगेल्स	50.00
37. रूपवती वासिलीसा–अद्भुत रूसी लोक कथायें		
38. बच्चों सुनो कहानी!	लेव तोलस्तोय	175.00
39. जहां चाह वहां राह	उजबेक लोक कथाएं	170.00
40. पापा–जब बच्चे थे	अलेक्सांद्र रास्किन	100.00

आर्डर भेजें:
पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड
5–ई, रानी झांसी मार्ग
नई दिल्ली–110055
दूरभाष: 011–23523349, 23529823
ईमेल: pph5e1947@gmail.com
https//pphbooks.net

दिल्ली के शोरूम
जी–18, आउटर सर्कल, कनाट प्लेस
नई दिल्ली–110001, फोन: 23324064
पीपीएच बुकशॉप, जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी के पास,
नई दिल्ली–110 067, फोन: 65447645
पीपीएच शॉप, अजय भवन
15, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त मार्ग, नई दिल्ली–2

नोट: आप भेज सकते हैं:
चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक मनिआर्डर ''पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड'' के पक्ष में
बैंक विवरण:
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट: 32074674284, आई.एफ.सी. कोड: SBIN0009371

आरपीडी: भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के ...

पेज 5 से जारी...

अलावा सरदार पटेल समेत कार्यसमिति के 7 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया।

पहले सुभाष चन्द्र बोस ने नेहरू की कम्युनिस्ट हमदर्दी की आलोचना की लेकिन बाद में आरपीडी से बात करने के बाद उन्होंने अपने विचार बदल दिए। उनकी मुलाकात आरपीडी से लंदन में 1938 में हुई थी। इसकी एक रिपोर्ट **लेबर मंथली** में 24 जनवरी 1938 को प्रकाशित की गई। इसे सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक **इंडियन स्ट्रगल 1920–40** में प्रकाशित भी किया।

बोस ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मार्क्स और लेनिन ने कम्युनिज्म जिस रूप में प्रस्तुत किया है वह सही है। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल आजादी के आंदोलन का समर्थन करता है। कांग्रेस को व्यापक साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चे में बदलने करने का प्रस्ताव भी रखा।

सुभाष चंद्र बोस ने 11 जनवरी 1938 को लंदन के सेंट पैंक्रियाज हाल में आरपीडी की अध्यक्षता में एक सभा को संबोधित किया।

बोस ने स्पष्ट किया कि उन्हें ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी प्रोत्साहन मिला है।

चुनाव में हिस्सा लेना

आरपीडी ने बर्मिंघम से ब्रिटिश पार्लमेंट के लिए एमरी के खिलाफ चुनाव लड़ा। उस समय ऐमरी सेक्रेटरी आफ इंडिया थे और स्वतंत्रता सेनानियों पर दमन के लिए बदनाम थे। सीपीजीबी ने जानबूझकर आरपीडी को खड़ा किया ताकि साम्राज्यवाद के खिलाफ और भारत की आजादी के आंदोलन के पक्ष में समर्थन स्पष्ट कर सकें। इस एस ए डांगे ने आरपीडी के लिए बर्मिंघम में चुनाव प्रचार किया।

भारत में आरपीडी

रजनी पाम दत्त 1946 में डेली वर्कर की ओर से कैबिनेट मिशन को कवर करने के लिए भारत आए। उनका कलकत्ता में भारी स्वागत किया गया। यह शहर उनके वंशजों का शहर था। उन्हें मई दिवस की रैली तथा अन्य मीटिंगों में शामिल होने और बोलने का मौका मिला जिनमें केसोराम काटन मिल गेट मीटिंग भी शामिल थी।

हीरेन मुखर्जी लिखते हैं हालांकि यह देश उनका जन्म स्थान नहीं था लेकिन पितृ देश अवश्य था। वे रामबगान परिवार के दत्त परिवार के चमकते सितारे थे जिन्होंने बिना हिचक कम्युनिज्म को अपना लिया।

आरपीडी का 50 वां जन्मदिन बम्बई में मनाया गया। वे बड़े ही खुश हुए।

उनकी मुलाकात देश के महत्वपूर्ण नेताओं से हुई जैसे सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, एस के पाटिल, सी राजगोपालाचारी, नेहरू, गांधीजी, अबुल कलाम आजाद तथा अन्य। उन्होंने इन यात्राओं के बारे में लेबर मंथली में विस्तार से लिखा। उन्होंने सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने मजबूती से देश के विभाजन और पाकिस्तान के गठन के प्रस्ताव का विरोध किया।

उन्होंने सोशलिस्ट नेता मधु लिमये से लंदन में नवंबर 1947 में एक इंटरव्यू में कहा कि वे कांग्रेस में बने रहें और कम्युनिस्टों को शामिल करने का प्रयत्न करते रहें।

बीटीआर काल और आरपीडी

आरपीडी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बीटी रणदिवे के नेतृत्व में स्वीकृत संकीर्णतावादी एवं दुस्साहसिक लाइन अपनाये जाने से काफी चिंतित थे। आरपीडी ने नेहरू की विदेश नीति और कुछ आंतरिक नीतियों की प्रशंसा की। उन्होंने भारतीय कम्युनिस्टों से अपनी लाइन पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने 'कॉमिन्फॉर्म' की पत्रिका एल पी पी डी (अर्थात स्थाई शांति और पीपुल्स डेमोक्रेसी के लिए) अपने एक लेख में तीसरी दुनिया के देशों में आजादी के नए आयामों और नए परिप्रेक्ष्य की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने भारतीय आजादी की रक्षा करने तथा प्रतिक्रियावादी बड़े पूंजीवाद एवं सामंतवाद के खिलाफ संघर्ष करने तथा भूमि सुधारों के लिए जोर दिया। साथ ही देश की रक्षा के लिए सभी प्रगतिशील शक्तियों को एक जगह आने का आवाहन किया।

उनके इस लेख पर भाकपा के अंदर बड़ी तीव्र बहस हुई। इस लेख से चरम वामपंथी रास्ते को छोड़ने में सहायता मिली। भाकपा की केंद्रीय समिति ने स्वीकार किया कि आर पीडी ने पार्टी को सही रास्ते पर लाने और संकीर्णता वादी भयंकर भूलो को सुधारने मैं सहायता की।

आरपीडी ने कोरियाई युद्ध में नेहरू की भूमिका को भी सराहा। (लेबर मंथली नवंबर 1950)

पार्टी ने कहाकि आरपीडी और सीपीजीबी ने कई मौकों पर हमारी समझ को सही रास्ते पर लाने में मदद की है। इनमें 1933 की तीन पार्टियों का पत्र, 1936 का दत्त ब्रेडले थिसिस, 1939 का सीपी जीबी का पत्र इत्यादि शामिल हैं।

सशस्त्र संघर्ष के खिलाफ

आरपीडी ने जोर दिया कि 1948 से 50 का सशस्त्र संघर्ष आत्मघाती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शांति के सवाल पर संघर्ष किया जाए और नेहरू का समर्थन किया जाए। 1951 में भाकपा ने उनसे कई सवाल किए जिनका उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया। इससे आरपीडी कि सृजनात्मक सोच का पता चलता है। उन्होंने 1954 में **एल पी पी डी** में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के नए पहलुओं के बारे में लिखा और इस बात को रेखांकित किया कि शांति के लिए संघर्ष तथा आजादी की लड़ाई एक दूसरे से अलग नहीं है। उन्होंने मजदूरों, किसानों, बुद्धिजीवियों, शहरी निम्न पूंजीपतियों तथा राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग को साम्राज्यवाद विरोधी जनतांत्रिक क्रांति में शामिल करने पर जोर दिया।

असाधारण सिद्धांतकार

आरपीडी असाधारण गुण संपन्न सिद्धांतकार थे और घूमते फिरते एनसाइक्लोपीडिया। उनका दैनिक रूटीन बड़ा ही नियमित था। शोध कार्य में वे बड़े ही नियमित और ध्यान पूर्वक काम किया करते। विभिन्न विषयों पर ढेर सारे रिसर्च कार्ड रखा करते।

उन्होंने बड़ी संख्या में लेख, पुस्तक समीक्षा, पुस्तिकाएं एवं पुस्तकें लिखी। इनका असर सारी दुनिया के कम्युनिस्ट आंदोलन पर पड़ा। वह बिना हस्तक्षेप किए अन्य पार्टियों की समस्याओं को सुलझाने में मदद किया करते।

आरपीडी 1960 के दशक के मध्य में राजनीति से रिटायर कर गए और पार्टी के सारे पद छोड़ दिए। लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा। वे लंबे समय तक बीमार रहे। उनकी मृत्यु लंदन में 20 दिसंबर 1974 को हो गई।

भारत में उभरता साम्यवाद व पेशावर षडयंत्र...

पेज 12 से जारी...

बंद हो गया तो वह अन्य छात्रों के साथ मॉस्को शिफ्ट हो गया जहां उसने पूर्व के मेहनतकशों के कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय में एक वर्ष तक अध्ययन किया। उसके बाद वह भारत आने के लिए 10 दिसंबर 1923 को सियस्तान (ईरान) में ब्रिटिश कौन्सुलेट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बेड़ियों से बांध कर उसे भारत लाया गया और उस पर उन्हीं आरोपों के तहत मुकदमा चला जो अन्य पर लगाए गए थे और उसे तीन साल की सजा हुई।

जेल रिहा होने के बाद अधिकांश अभियुक्त राजनीति में काम करते रहे। अकबर शाह ने पढ़ाई शुरू कर दी तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय से एल. एल.बी.की डिग्री लेकर नौशेरा में प्रैक्टिस शुरू कर दी। बाद में सरहदी गांधी अब्दुल गफ्फार खाँ की संस्था खुदाई खिदमतगार में काम किया तथा नेता जी सुभाषचंद्र बोस द्वारा बनाई गई राजनैतिक पार्टी ''ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक' में शामिल हो गए। सन् 1910 में नेता जी के कलकत्ता से बर्लिन भागने की योजना बनाने व कार्यान्वित करने में अकबर शाह की मुख्य भूमिका थी। उनके एक मित्र भगतराम तलवार जिनका संबंध भारत की कम्युनिस्ट पार्टी से था, ने नेता जी को भारत की सीमा से निकाल कर अफगानिस्तान की सीमा में घुसने के मामले में मदद की। भगतराम तलवार का जिक्र प्रसिद्ध कम्युनिस्ट एवं ट्रेड यूनियन नेता एस. ए. डांगे ने अपने एक साक्षात्कार में जिक्र भी किया है। साक्षात्कार के अनुसार, डांगे उस समय जेल में थे और उन्होंने ही भगतराम का नाम सुझाया था क्योंकि वह उस इलाके से ''भली–भांति'' परिचित था। उसे यह पता नहीं था कि जिस आदमी के साथ वह जा रहा है–वह कौन है?

भगतराम तलवार ने भी माना है कि उन्हे कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से भी इस काम को करने की सूचना मिली थी। डांगे के अनुसार जब सरकार को सुभाषचंद्र बोस के बर्लिन पहुंचने का पता चला तो भारत में काफी सख्ती हो गई जिस कारण भगतराम अफगानिस्तान से वापस न आ सके। उनकी शादी कुछ ही रोज पहले हुई थी। उनकी पत्नी को परिवार व रिश्तेदारों ने दूसरी शादी करने की सलाह दी परंतु वह राजी नहीं हुई। उसने इंतजार किया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया तब जाकर भगतराम वापस आए। परिवार दरियागंज दिल्ली में एक कम्यून में रह रहा था जब दोनों मियां–बीवी आमने–सामने आए तो एक दूसरे को पहचान तक न सके। डांगे आगे कहते हैं कि अब परिवार के सामने रोजी–रोटी का प्रश्न था, अतः उन्होंने (डांगे ने) देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से कह कर बरेली (उत्तर प्रदेश) में खेती के लिए एक फार्म का आवंटन करवाया। दूसरी ओर, अकबर शाह को इस बाबत कई सजाएं काटनी पड़ी (1941–45 तक)। 1951 में वह प्रान्तीय विधान सभा के सदस्य चुने गए। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें ''आजादी की तलाश'' पेशावर षडयंत्र केसों के मामले में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

मीर अब्दुल मजीद जेल की रिहाई के बाद 26 दिसंबर 1925 में हुई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पहली कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। वह उन नौजवानों में भी शामिल थे जिन्होंने भगतसिंह के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की तथा सोहन सिंह जोश के साथ मिलकर अप्रैल 1928 में पंजाब में कीर्ति किसान पार्टी बनाई। 1927 में वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यकारिणी के लिए चुने गए। गौहर रहमान, जा तीसरे पेशावर षडयंत्र मुकदमें में दो वर्ष की सजा काट चुके थे, इस बैठक में एस. ए.डांगे, मुज्जफर अहमद और ए.एस. के अयंगर के साथ अध्यक्षमंडल के लिए चुने गए। मीर अब्दुल अहमद मेरठ षडयंत्र केस में भी अभियुक्त थे। फिरोजुद्दीन मन्सूर भी जेल से रिहा होने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी में काम करने लगे। उन्हें 1928 में कलकत्ता में हुई ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेन्ट्स पार्टी की कॉन्फ्रेंस में घाटे, डांगे, जोगलेकर आदि के साथ कार्यकारिणी के लिए चुना गया। भारत विभाजन के बाद वह पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के पहले महासचिव बने। भोपाल के रफीक अहमद भी कुछ समय तक दिल्ली पार्टी में काम करते रहे। फजल इलाही कुर्बान ने ट्रेड यूनियन फ्रंट पर पंजाब में काम किया लेकिन बाद में वह भी पाकिस्तान चले गए।

पुस्तक की भाषा अत्यंत सरल है। पुस्तक में उन सभी नौजवानों का विवरण विस्तार से दिया गया है, जो इस आंदोलन में शरीक थे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया, किस प्रकार के कष्ट झेले, किस तरह मास्को व ताशकंद इसमें उनकी शिक्षा–दीक्षा हुई आदि का विस्तार से रोचक वर्णन किया गया है। आजादी के बाद वर्षो तक कांग्रेस सत्ता में रही। उन्होंने आजादी के आंदोलन में कम्युनिस्टों के योगदान व बलिदानों का वर्णन ईमानदारी से नहीं किया, जिस कारण इतिहास में उन्हें जो स्थान मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। पार्टी के अधिकतर कैडर भी अपने गौरवशाली इतिहास से अनभिज्ञ है। अतः इस प्रकार की पुस्तकों के प्रकाशन की अत्यधिक आवश्यकता है।

लेखक आर.एस. यादव पार्टी हिन्दी साप्ताहिक ''मुक्ति संघर्ष'' के पूर्व संपादक हैं। समसामयिक लेखों के अलावा, ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक श्रमिक आदि विषयों पर उनकी कई पुस्तकें छप चुकी हैं। अपने लेखों में वह मजदूरों की समस्याओं के बारे में भी काफी मुखर रहते हैं।

आशा है कि पुस्तक पाठकों को अवश्य पसंद आएगी तथा शोधकर्ताओं के लिए भी काफी लाभदाय सिद्ध होगी।

मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक 6 – 12 नवम्बर, 2022

Delhi Postal Regd. No. DL(C)-01/1277/2021-23
Licenced to Post without Pre-payment. U(C)-102/2021-23
(R.N.I. No. 20196/70) Posted in LPC, DRMS, Friday & Saturday

प्रकाशन तिथि: 4.11.2022

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं पार्टी कांग्रेस

नव निर्वाचित भाकपा का राष्ट्रीय नेतृत्व

कन्ट्रोल कमीशन

1. रामेन्द्र कुमार
2. शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बिहार)
3. डा. नारा सिंह
4. पी. दुर्गा भवानी (महिला) आंध्र प्रदेश
5. सत्येन मुकेरी (केरल)
6. राम बहेती (महाराष्ट्र)
7. हरदेव सिंह अर्शी (पंजाब)
8. थिरीचे एम. सेल्वाराज (तमिलनाडु)
9. मोती लाल (उत्तर प्रदेश)
10. निशा सिद्धू (महिला)
11. मो. युसुफ (तेलंगाना)

राष्ट्रीय परिषद सदस्य

केन्द्र

1. डी. राजा
2. अतुल कुमार अनजान
3. अमरजीत कौर
4. बिनॉय विश्वम
5. डा. के. नारायणा
6. पल्लब सेनगुप्ता
7. डॉ. बी. के. कांगो
8. नागेन्द्रनाथ ओझा
9. अजीज पाशा
10. एनी राजा
11. सी. एच. वेंकटाचलम
12. आर. वेंकैया (किसान सभा)
13. पी. संदोष कुमार
14. एस. वी. दामले
15. अनिल राजिमवाले
16. कृष्णा झा
17. सी. श्रीकुमार
18. के. श्रीनिवास रेड्डी
19. विद्यासागर गिरि
20. गुलजार सिंह गोरिया
21. डॉ. ए. ए. खान
22. विक्की महेश्वरी (एआईएसएफ)
23. थिरूमलाई (एआईवाईएफ)
24. डा. अरूण मित्रा
25. रायकुट्टी
26. प्रो. अरूण कुमार (एआईएफयूसीटीओ)
27. के. रामाकृष्णा
28. मुप्पला नागेश्वर राव
29. जे. वी. सत्यनारायण मुर्ति
30. जी. ओबुलेसु
31. ए. वानजा (महिला)
32. टी. मधु
33. के. शिवा रेड्डी
34. कनक गोगोई
35. मुनीन महंता
36. राम नरेश पाण्डेय
37. जानकी पासवान
38. राजेन्द्र सिंह
39. अवधेश राय
40. ओमप्रकाश नारायण
41. प्रमोद प्रभाकर
42. राजश्री किरन (महिला)
43. निवेदिता झा (महिला)
44. मिथलेश झा
45. संजय कुमार
46. मनीष कुंजाम
47. सत्यनारायण कमलेश
48. मन्जु केवासी (महिला)
49. दिनेश सी वैष्णण
50. क्रिस्टोफर फोंसेका
51. विजय सेनमारे
52. दरियाव सिंह कश्यप
53. भाग सिंह चौधरी
53. महेन्द्र पाठक
55. महादेव राम
56. कनईमल पहावा
57. पी. के. पांडेय
58. साथी सुन्दरेश
59. विजया भास्कर
60. कानम राजेन्द्रन
61. के. प्रकाश बाबू
62. ई. चन्द्रशेखरन
63. जे. चिन्चू रानी (महिला)
64. राजाजी मैथ्यू थॉमस
65. के. पी. राजेन्द्रन
66. के. राजन
67. पी. प्रसाद
68. जी. आर. अनिल
69. चित्तयम गोपाकुमार
70. पी. पी. सुनीर
71. एड. पी. वासन्थम (महिला)
72. रिक्त
73. अरविंद श्रीवास्तव
74. हरिद्वार सिंह
75. तुकाराम भस्मे
76. सुभाष लान्डे
77. शिवकुमार गनवीर
78. राजन क्षीरसागर
79. एल. थोरियन
80. एस. मेमसाना
81. समुद्र गुप्ता
82. अभय साहु
83. आशीष कानूनगो
84. राम कृष्ण पांडा
85. खिर्द सिंहदेव
86. ए. एम. सलीम
87. आई. दिनेश पोन्नैया
88. बंत सिंह बरार
89. जगरूप सिंह
90. निर्मल सिंह धालीवाल
91. पृथीपाल सिंह माड़ीमेघा
92. अमरजीत सिंह असल
93. नरिन्दर सोहेल
94. नरेन्द्र आचार्य
95. सुनीता चतुर्वेदी
96. इरा मुथुरासन
97. एन. पेरियासामी
98. एम. वीरप्नदीन
99. टी. एम. मुर्ति
100. के. सन्तानाम
101. एम. अरूमुगन
102. वी. शिवापुन्नीयम
103. वहीदा निजाम (महिला)
104. टी. रामासामी
105. एम. कन्नकी (महिला)
106. चडा वेंकट रेड्डी
107. कुन्नामनेनी सम्बाशिवा राव
108. पल्ला वेंकटा रेड्डी
109. पश्य पदमा (महिला)
110. टी. श्रीनिवास राव
111. के. शंकर
112. बालानरसिम्हा
113. बी. हेमलता राव
114. डॉ. युधिष्ठर दास
115. डॉ. गिरीश शर्मा
116. अरविंदराज स्वरूप
117. इम्तियाज अहमद
118. क्रांति मिश्रा
119. समर भंडारी
120. स्वप्न बनर्जी
121. प्रबीर देव
122. उज्जवल चौधरी
123. तरूण दास
124. भारती अधिकारी (महिला)
125. तपन गांगुली

उम्मीदवार सदस्य

126. राकेश शर्मा (जम्मू)
127. जी. एम. मिजराब (कश्मीर)
128. शंकर लाल (दिल्ली)
129. सोमन पिल्लई (गुजरात)
130. टी. टी. जिस्मोन (केरल)
131. ई. टी. नरसिम्हा (तेलंगाना)
132. मित्रा वाशु (केन्द्र)
133. महेश राठी (मुक्ति संघर्ष)
134. एन. चिदम्बरम (न्यू एज)
135. शुवम बनर्जी (एआईएसएफ)
136. सुखजिन्दर माहेसरी (एआईवाईएफ)
137. इप्टा
138. पीडब्लूए

राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य

1. डी. राजा (महासचिव)
2. कानम राजेन्द्रन
3. अतुल कुमार अनजान
4. अमरजीत कौर
5. के. नारायणा
6. डा. बी.के. कांगो
7. बिनॉय विश्वम
8. पल्लब सेनगुप्ता
9. नागेन्द्रनाथ ओझा
10. अजीज पाशा
11. रामकृष्ण पांडा
12. एनी राजा
13. डा. गिरीश शर्मा
14. मनीष कुंजाम
15. पी. संदोष कुमार
16. के. प्रकाश बाबू
17. सी.एच. वेंकटाचलम
18. राम नरेश पाण्डेय
19. जानकी पासवान
20. के. शम्बाशिव राव
21. चडा वेंकटा रेड्डी
22. के. रामाकृष्णा
23. मुनीन महंता
24. ए. वानजा
25. आर. वेंकैया (एआईकेएस)
26. गुलजार सिंह गोरिया
27. टी.एम. मुर्थी
28. आर. मुथरासन
29. स्वप्न बनर्जी
30. बंत सिंह बरार
31. रिक्त
32. रमेन्द्र कुमार (कन्ट्रोल कमीशन का चेयरमैन होने के नाते कायकारिणी में रहेंगे)

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से डी. राजा द्वारा BFL Infotech Ltd. (Media Division), C-9, Sector-3, Noida, Dist. Gautam Budh Nagar, UP द्वारा मुद्रित, अजय भवन, 15–कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली–110 002 से प्रकाशित। **संपादक**: रणबीर सिंह यादव फोन: 011–2323 0762 फैक्स 91–011–2323 5543.
e-mail: newagemukti@gmail.com, Layout: Udai Bhan Rajbhar.